A Daily News Magazine
भोपाल
सोमवार, 20 जुलाई, 2026
भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 23, अंक 318, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2
सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

इसरो से बड़ी संख्या में वैज्ञानिक इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं?

इमरान क़ुरैशी?

देश के स्पेस स्टार्टअप्स का बढ़ता असर अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो तक पहुँच गया है। स्टार्टअप सेक्टर ने देश में कई क्षेत्रों में नए मानक स्थापित किए हैं, लेकिन अब इसने प्रतिष्ठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को भी झकझोर दिया है। अब अंतरिक्ष विभाग ने अपने वैज्ञानिकों के इस्तीफ़े स्वीकार करने के नियमों में बदलाव किया है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि पिछले एक साल में अनुमानित 100-120 वैज्ञानिक इसरो छोड़कर स्पेस स्टार्टअप्स से जुड़ गए हैं।

केंद्र सरकार के इस विभाग ने एक ऑफिस मेमोरेंडम में कहा है कि उसने गगनयान और अन्य अहम मिशनों या परियोजनाओं से जुड़े ग्रुप 'ए' के वैज्ञानिक के अलावा तकनीकी कर्मियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) और इस्तीफ़े के अनुरोध को अब सामान्य प्रक्रिया के तहत स्वीकार नहीं करने का फ़ैसला किया है। यानी इसरो के अलग-अलग केंद्रों के निदेशकों या प्रमुखों के पास इस्तीफ़ा स्वीकार करने का अधिकार अब नहीं रहेगा।

विभाग ने कहा है कि 'साइंटिस्ट/इंजीनियर-एसजी रैंक से नीचे के अधिकारियों के मामलों में भी संबंधित केंद्रों के निदेशक या यूनिट हेड अपनी स्पष्ट सिफ़ारिशों के साथ प्रस्ताव विभाग को भेजेंगे, जहाँ अंतिम फ़ैसला लिया जाएगा।'

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) के लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (एलवीएम-3) परियोजना निदेशक विक्टर जोसेफ़ भी शामिल हैं। बताया जाता है कि इसरो के सभी केंद्रों में से यूआर राव सैटेलाइट सेंटर ने अपने 14 हजार 600 वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक खोए हैं।

भारत की प्रमुख अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्था के इस फ़ैसले ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बीच बहस छेड़ दी है कि स्टार्टअप्स के ज़रिए स्पेस सेक्टर मज़बूत कैसे होगा और क्या इस तरह प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को दूसरे संस्थानों की ओर से आकर्षित किया जाना उचित है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी. माधवन नायर का कहना है कि यह स्थिति आईटी क्रांति के दौरान पैदा हुई थी और यह उसी का दोहराव है। इस तरह की प्रक्रिया इसरो की गतिविधियों पर गंभीर असर डाल सकती है।'

उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि इस तरह प्रतिभाओं को दूसरे संस्थानों में जाना नहीं होना चाहिए। इस इंडस्ट्री को बढ़ने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन्हें अपने लोगों की भर्ती और ट्रेनिंग ख़ुद करना चाहिए, न कि इसरो जैसी स्थापित संस्थाओं से अनुभवी पेशेवरों को ले जाना चाहिए।' हालांकि, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक सचिव पी.जी. दिवाकर इसरो छोड़ने वाले वैज्ञानिकों की संख्या से हैरान नहीं हैं। उनका मानना है कि पहले इसरो बड़ी संख्या में अर्थ ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन सैटलाइट लॉन्च करता था, लेकिन 'आज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटलाइट की कमी है। सरकार की पूरी नीति बदल गई है। पहले सरकार इसरो को रिसोर्ससैट, कार्टोसैट और ओशनसैट जैसी परियोजनाओं के लिए पैसे देती थी। इसरो सामाजिक हित में ये सैटलाइट बनाता था। लेकिन अब सरकार ने अलग-अलग मंत्रालयों से कहा है कि वे अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपने सैटलाइट ख़ुद लॉन्च करें।'

उनका मानना है कि मंत्रालयों को सामाजिक हित के लिए उपग्रहों में निवेश की ज़रूरत समझने में अभी कुछ समय लगेगा। हालांकि, उन्हें यह भी उम्मीद है कि भारत में स्पेस स्टार्टअप्स तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, 'फ़िलहाल वैज्ञानिकों को यह एक आकर्षक विकल्प लग रहा है।'

लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टार्टअप्स में वैज्ञानिकों को वैसा वैज्ञानिक विकास मिलेगा, जैसा इसरो जैसी संस्था में मिलता है? दिवाकर का कहना है कि शुरुआत में शायद ऐसा अवसर न मिले, लेकिन 'अगर स्टार्टअप्स आगे बढ़ते हैं तो वैज्ञानिकों को भी फ़ायदा होगा और यह सिर्फ़ कमाई तक सीमित नहीं रहेगा।'

वहीं माधवन नायर इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है, 'प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा सैलरी दे सकता है, लेकिन वहाँ उतने चुनौतीपूर्ण वैज्ञानिक काम नहीं होंगे। उन्होंने इस सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार किया कि क्या इसरो के भीतर मौजूद किसी व्यवस्थागत समस्या के कारण वैज्ञानिक प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने माना कि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सैलरी के बीच बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा, 'यह बहुत ख़ास सेक्टर है, जहाँ असाधारण प्रतिभा वाले लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसी प्रतिभा को बनाए रखने के लिए सरकार को ख़ास प्रयास करने होंगे। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं ख़त्म हुईं।'

माधवन नायर ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 'हम सरकार को यह समझाने में सफल रहे थे कि स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टरों को अन्य सरकारी नौकरियों से अलग माना जाना चाहिए।' इसके बाद परफॉर्मेंस आधारित प्रोत्साहन योजना, नक़द इनाम योजना और स्पेशल सैलरी वृद्धि जैसी कई योजनाएं शुरू की गई थीं। समय के साथ इनमें से कई योजनाएं धीरे-धीरे वापस ले ली गईं।' नायर ने कहा, 'इन फ़ैसलों को लेने वाले कुछ लोग शायद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जटिलताओं और उसकी मांगों को पूरी तरह नहीं समझते।'

एक समय था जब इसरो कम्युनिकेशन सैटलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटलाइट बनाने के साथ-साथ चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी संचालित कर रहा था। दिवाकर कहते हैं, 'आज तस्वीर बदल चुकी है। आज आपके पास पिक्सेल, स्काईरूट, अग्निकुल, गैलेक्सआई जैसी कंपनियां हैं। मैं ऐसे 10-15 बेहतरीन स्पेस स्टार्टअप्स के नाम गिना सकता हूँ, जो विदेशी निवेश भी आकर्षित कर रहे हैं।' जनवरी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया था कि भारत की स्पेस इकॉनमी बढ़कर लगभग 8.4 अरब डॉलर तक पहुँच गई है और देश में 399 स्पेस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स लॉन्च व्हीकल, सैटलाइट, प्रोपल्शन सिस्टम और स्पेस-ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में पत्रकारों को बताया, 'प्रशासनिक कारणों से यह मेमो तैयार किया गया है, ताकि इस पर कहीं अधिक परिपक्व स्तर पर निर्णय लिया जा सके। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि वैज्ञानिकों के आने-जाने का परियोजना पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।'

सरकार ने 2019 में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथोराइजेशन सेंटर (इन-स्पेस) की स्थापना के साथ स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था। यह संस्था प्राइवेट सेक्टर और इसरो जैसी सरकारी एजेंसियों के बीच एक सिंगल-विंडो इंटरफेस के रूप में काम करती है। इसरो के अधिकारियों की प्रतिक्रिया मिलने के बाद इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा। इसरो के एक अधिकारी, जिन्हें मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं है, ने बताया कि अध्यक्ष वी. नारायणन दिल्ली में हैं और मीडिया से बात करने के लिए उन्हीं को अधिकृत किया गया है।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जगदीशपुर में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय

यूसीसी बिल को मंजूरी

तलाक, तलाक, तलाक बोलने से नहीं होगा तलाक

भोपाल (नप्र)। जगदीशपुर में आयोजित मोहन कैबिनेट की मीटिंग में कई ऐतिहासिक और अहम फैसले हुए हैं। कैबिनेट ने यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी है। मानसून सत्र में इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने बिल को मंजूरी देने के बाद इसकी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों के लिए मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही शादी की इजाजत है।

अनुसूचित जनजातियों को मिला संरक्षण- यूसीसी के कुछ कठोर नियमों से अनुसूचित जनजातियों को दूर रखा गया है। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366 (खंड 25) के तहत आने वाली अनुसूचित जनजातियां पर लागू नहीं होगा। इसमें भील, गोंड, कोरकू, बैगा, सहरिया और भारिया हैं।

यूसीसी की अहम बातें- एक ही शादी को मंजूरी- यह कानून सभी समुदायों में केवल एक ही शादी को अनिवार्य बनाता है। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही जीवित जीवनसाथी के साथ शादीशुदा रह सकता है।

शादी की उम्र कोई बदलाव नहीं- विवाह के लिए पुरुषों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष तय की गई है। तीन तलाक बोलकर तलाक नहीं- अब मौखिक तलाक और अनौपचारिक पंचायत के फैसलों को पूरी तरह गैर-कानूनी घोषित किया गया है। अब विवाह का समापन केवल कानून में बताए गए स्पष्ट और वैधानिक आधार पर ही होगा।

लिव-इन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए साथ रहने की शुरुआत के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के पास लिव-इन रिलेशनशिप का बयान जमा करना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। पार्टनर्स की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। वे प्रतिबंधित श्रेणी में न हों, पहले से विवाहित न हों और उनकी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। यदि कोई पार्टनर 21 साल से कम उम्र का है, तो लिव-इन के शुरू होने और खत्म होने की जानकारी उनके माता-पिता-अभिभावकों को भेजी जाएगी।

गर्भावस्था के आधार पर सामान अधिकार- अब महिलाओं को भी यह अधिकार दिया गया है कि यदि उनके पति ने शादी के समय किसी दूसरी महिला को गर्भवती किया है तो पत्नी शादी को रद्द घोषित करने की मांग कर सकती है।

शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य- एमपी के निवासियों के लिए शादी और तलाक दोनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। शहरी क्षेत्रों में एमपी ई-नगर पालिका पोर्टल और ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, नगरपालिका या पंचायत के जरिए यह प्रक्रिया पूरी होगी। रजिस्ट्रेशन न होने पर शादी अमान्य नहीं होगी लेकिन रजिस्ट्रार द्वारा बिना ठोस लिखित कारण के आवेदन खारिज करने पर जुर्माना होगा।

हलाला पर भी रोक- तलाक के बाद दोबारा शादी के नाम पर हलाला जैसी प्रथा को दंडनीय अपराध माना गया है।

लिव-इन के बच्चे माने जाएंगे वैध

लिव-इन से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाएगा और उन्हें पूर्ण उत्तराधिकार मिलेगा। यदि पुरुष पार्टनर महिला को छोड़ देता है, तो वह सक्षम अदालत के माध्यम से कानूनी पत्नी की तरह ही भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) का दावा कर सकती है। बिना रजिस्ट्रेशन एक महीने से ज्यादा साथ रहने पर 3 महीने तक की जेल या 10,000 जुर्माना हो सकता है। गलत जानकारी देने पर 3 महीने की जेल और 25,000 जुर्माना तथा रजिस्ट्रार के नोटिस के बाद भी बयान न देने पर 6 महीने तक की जेल और 25,000 का जुर्माना हो सकता है।

कांग्रेस इसे हिंदू-मुस्लिम के चश्मे से देखती

सीएम मोहन यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर हमनें सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे जिसमें आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के जनप्रतिधिन शामिल हुए लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि नहीं आए। कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुस्लिम को राजनीतिक चश्मे से देखती है। उन्हें एक देश, एक निशान,एक प्रधान पर हमेशा दुविधा रहती है। जब हमने सबके सुझाव मांगे तो 80 प्रतिशत मुस्लिम बहनों ने इसके पक्ष में अपनी अपनी बात कही।

राम-रहीम के होंगे एक अधिकार

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि ऐसा कानून लागू किया जाए, जिसमें राम, रहीम, रवींद्र और रॉबिन सभी को समान अधिकार और समान न्याय मिले।

उत्तराधिकार को लेकर एक समान नियम- वहीं, यूसीसी में बेटों और बेटियों को संपत्ति के उत्तराधिकार में समान अधिकार दिए गए हैं। चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो।

प्रदेश में 73 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन के लिए 898.96 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में गौंड वंश के वैभवशाली दुर्ग जगदीशपुर के चमन महल में समानता और न्याय की भावना को समर्पित मंत्रि-परिषद की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदन किया।मंत्रिपरिषद ने 8 अन्य विधेयकों को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने के लिए भी अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद के एक अन्य निर्णय में प्रदेश के 73 अस्पतालों के उन्नयन को भी मंजूरी दी गई है।मंत्रिपरिषद ने इस कार्य के लिए 898 करोड़ 96 लाख रुपए भी स्वीकृत किए हैं।

मानसून सत्र से पहले तीन घंटे चली सर्वदलीय बैठक

40 पार्टियां शामिल, रिजिजू बोले-सबने अपनी बात रखी

नई दिल्ली (एजेंसी)। मानूसन सत्र से एक दिन पहले रविवार को संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में सर्वदलीय बैठक हुई। 3 घंटे चली मीटिंग की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके सहित 40 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि बैठक के बीच विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों के गुट को बैठक में क्यों बुलाया, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने उनके गुट को अभी तक मान्यता नहीं दी है। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को हस्ताक्षरित आवेदन देकर नए दल के रूप में मान्यता और संसद में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। यह मामला स्पीकर के विचाराधीन है। जब मामला स्पीकर के पास है और 20 सांसदों का समूह मौजूद है, तो उन्हें सर्वदलीय बैठक में कैसे नहीं बुलाया जा सकता। लोकसभा सभी की है।

पीवी सिंधु जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनीं

- 2 साल बाद कोई टाइटल जीता, यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया

टोक्यो (एजेंसी)। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर-750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। वे यह टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया। यह मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी।

सुप्रभात

उन्हें शायद पता नहीं कि स्याही
सिर्फ़ समय की इबारत लिखने के काम आती है
काग़ज पर लिखी जाए अथवा दीवार पर
फैंक दी जाए किसी के चेहरे पर
कि छिड़क दी जाए किसी की उजली कमीज़ पर
उड़ेल दी जाए ज़मीन पर
स्याही गढ़ लेती है अपना मुहावरा अपनी भाषा
भाषाओं को दरकार होती है स्याही की
लेक़िन स्याही
कभी मोहताज नहीं होती किसी भाषा की
उन्हें शायद पता नहीं
कि एक कवि नमक की खोज में निकला था
और रात ने उसे गिराया
स्याही के ताल में
उन्हें शायद पता नहीं
कि एक अन्य कवि बहुत कुछ कहना चाहता है
लेक़िन समय और स्याही
उसके पक्ष में नहीं है
बावजूद इसके
वह बेइंतिहा प्यार करता है
समय और स्याही से।

-वसंत सकरगाए

सरकार-पुलिस से 3 दिन में जवाब मांगा, अंतरिम आदेश नहीं दिया

सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट बोला, प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने से किया इनकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग फिलहाल पूरी नहीं हो सकी। दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई तय की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति, चिकित्सा व्यवस्था और उनके इलाज को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनीं। सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि जे. आंग्मो ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्हें सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज कर परिवार की पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति मांगी है। याचिका में कहा गया है कि वांगचुक को उनकी इच्छा के विरुद्ध सरकारी अस्पताल में रखा जा रहा है और परिवार का वहां दिए जा रहे इलाज पर भरोसा नहीं है।

सिब्बल बोले-अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराना उनका अधिकार

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है और उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि वांगचुक न तो किसी डिटेंशन में हैं और न ही स्वतंत्र रूप से अस्पताल बदल पा रहे हैं। सिब्बल ने अदालत को बताया कि मेदांता अस्पताल उन्हें भर्ती करने के लिए तैयार है और एंबुलेंस की व्यवस्था भी की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि वांगचुक को अपने वकीलों से मिलने में दिक्कत हो रही है।

इलाज में कोई कमी नहीं, विशेषज्ञों की टीम कर रही निगरानी

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार याचिका पर कोई तकनीकी आपत्ति नहीं उठा रही है। उन्होंने 16 जुलाई के डिवीजन बेंच के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने अदालत को पहले ही भरोसा दिलाया था कि वांगचुक की सेहत पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार नजर रख रही है और उन्हें हर जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

सुबह सवेरे

भोपाल ■ सोमवार, 20 जुलाई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

प्रभाष प्रसंग– स्मृतियों का स्थायी स्मारक

गौरव अवस्थी

राजघाट स्थित बापू की समाधि के निकट गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के सत्याग्रह मंडप में जब भी प्रभाष प्रसंग आयोजित होता है, वह केवल एक स्मृति–समारोह नहीं रह जाता; वह विचारों, मूल्यों और पत्रकारिता के आत्मबोध का उत्सव बन जाता है। इस वर्ष 12 जुलाई को आयोजित 16वें प्रभाष प्रसंग ने भी इसी परंपरा को नए अर्थ दिए। अवसर था हिन्दी पत्रकारिता की द्वि–शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रभाष परंपरा न्यास द्वारा प्रभाष जी की जयंती पर प्रकाशित दसवीं पुस्तक 'पत्रकारिता का युगधर्म' का लोकार्पण का।

यह पुस्तक केवल पृष्ठों का संकलन नहीं है, बल्कि पत्रकारिता की उस नैतिक चेतना का दस्तावेज है, जिसे प्रभाष जोशी ने अपने लेखन से जिया। जनसत्ता, प्रथम प्रवक्ता और युगवार्ता में समय–समय पर प्रकाशित उनके 41 लेख इस ग्रंथ में संकलित हैं। इन लेखों में समाचारों की क्षणभंगुरता नहीं, बल्कि विचारों की दीर्घजीविता है; घटनाओं का विवरण नहीं, बल्कि पत्रकारिता का धर्म और उसका विवेक है।इस पुस्तक के पीछे प्रभाष जी के आत्मीय साथी और उनके सुयोग्य शिष्य पद्मभूषण रामबहादुर राय की प्रेरणा है, जबकि संपादन का दायित्व मनोज मिश्र ने निभाया है। यह उनका पाँचवाँ संपादकीय प्रयास है। विशेष रूप से 'विनोबा दर्शन' जैसी पुस्तक इस कड़ी को और अधिक मूल्यवान बना देती है। प्रभाष परंपरा न्यास ने प्रभाष जी के विस्तृत पत्रकारीय जीवन में बिखरे विचार–मोतियों को जिस धैर्य और निष्ठा से एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है, वह केवल

प्रशंसनीय ही नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के प्रति एक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व का निर्वाह भी है।

प्रभाष प्रसंग के माध्यम से प्रकाशित इन पुस्तकों में जनपक्ष केंद्र में है। जनसत्ता के संपादकीयों, अग्रलेखों और वैचारिक टिप्पणियों, प्रथम प्रवक्ता एवं युगवार्ता पत्रिका के लिए लिखे गए आलेखों में बिखरी हुई वह चेतना यहाँ एक सुसंगठित रूप में सामने आती है। इसलिए ये पुस्तकें केवल पत्रकारों या पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं जो समाज, लोकतंत्र और सार्वजनिक जीवन की धड़कनों को समझना चाहता है। प्रभाष जोशी किसी एक पेशे या वर्ग के नहीं थे। वे अपने समय की सामूहिक चेतना के प्रहरी थे।चंबल के डकैतों के आत्मसमर्पण का प्रसंग हो या अयोध्या में विवादित ढाँचे के विध्वंस के बाद उनका ऐतिहासिक प्रतिरोध—प्रभाष जी ने हर बार शब्दों की गरिमा और मौन की शक्ति, दोनों का अद्भुत संतुलन प्रस्तुत किया। हिन्दी पत्रकारिता में उनका वह 'काला संपादकीय' आज भी प्रतिरोध की सबसे सशक्त अभिव्यक्तियों में गिना जाता है। यद्यपि इस परंपरा का पहला उदाहरण 1931 में 'भविष्य' पत्रिका की संपादक लक्ष्मीदेवी ने प्रस्तुत किया था, जिन्होंने सभी संपादकों के जेल भेजे जाने के विरोध में संपादन की बागडोर संभालकर संपादकीय स्तंभ रिक्त छोड़ दिया था; किंतु प्रभाष जी ने उस मौन को और अधिक तीक्ष्ण बनाते हुए पूरा संपादकीय स्तंभ काला कर दिया। वह मौन नहीं, समय के अंत:करण की आवाज़ था।प्रभाष जोशी की पत्रकारिता किसी बाहरी दबाव या लोकप्रियता की आकांक्षा से संचालित नहीं होती थी। उसकी दिशा उनके भीतर अंकित नैतिक 'लक्ष्मण रेखा' तय करती थी। पाठकों के प्रति उनकी जवाबदेही उतनी ही गहरी थी, जितनी अपने अंत:करण के प्रति। यही कारण है कि उनका लेखन आज भी विश्वास की तरह पढ़ा जाता है। प्रभाष परंपरा न्यास द्वारा अब तक प्रकाशित सभी पुस्तकें केवल स्मृति–ग्रंथ नहीं, बल्कि अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की जीवित दस्तावेज़ हैं। वे प्रभाष जी का पता तो देती ही हैं, साथ ही उस दौर के समाज की आत्मा से भी परिचय कराती हैं। मेरा अपना सौभाग्य है कि चित्तौड़ से लेकर दिल्ली तक आयोजित प्रभाष प्रसंग के अधिकांश आयोजनों का साक्षी बनने का अवसर मुझे मिला। हर बार लौटते हुए यही अनुभव हुआ कि स्मृतियाँ तभी जीवित रहती हैं, जब वे विचारों में बदल जाएँ।शायद यही कारण है कि प्रभाष प्रसंग देश और दिल्ली के उन विरल आयोजनों में है, जहाँ आचार और विचार साथ–साथ चलते हैं। यहाँ औपचारिकता नहीं, आत्मीयता है; प्रदर्शन नहीं, साधना है; और स्मरण नहीं, जीवन–मूल्यों का पुनर्स्मरण है। सोलह वर्षों की इस सतत यात्रा में प्रभाष जी के संस्कारों की ऊष्मा, उनके स्वभाव की सहजता, लोकजीवन की सोंधी गंध और भारतीय आत्मा की उदारता निरंतर अनुभव की जा सकती है।

इन आयोजनों का सबसे स्थायी पक्ष वे पुस्तकें हैं, जो हर वर्ष एक नई वैचारिक निधि के रूप में हमारे हाथों में आती हैं। कहा भी गया है–अक्षर अक्षय हैं। चित्रलिपियों से आरंभ हुई अक्षर–यात्रा आज डिजिटल संसार तक पहुँच चुकी है, पर पुस्तकें आज भी स्मृतियों और विचारों का सबसे विश्वसनीय आश्रय हैं। व्यक्ति नश्वर होता है, किंतु उसके विचार पुस्तक बनकर काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं।

संक्षिप्त समाचार

फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के लिए केरल में छुट्टी

- आज बंद रहेंगे स्कूल,छात्रों की मांग पर सरकार का फैसला

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल के सामान्य शिक्षा विभाग ने फीफा विश्व कप फाइनल के कारण सोमवार को राज्य के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। शिक्षा विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि यह निर्णय उन छात्रों के अनुरोध पर विचार करने के बाद लिया गया जो फुटबॉल के प्रशंसक हैं और रविवार रात होने वाला विश्व कप फाइनल देखना चाहते हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह अवकाश सामान्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों पर लागू होगा। सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अवकाश की घोषणा की। मंत्री ने लिखा, 'बच्चों अब खुश हो?' उन्होंने कहा कि फुटबॉल प्रेमी छात्रों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए केरल सामान्य शिक्षा विभाग ने फीफा विश्व कप फाइनल के मद्देनजर सोमवार (20 जुलाई) को विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।

वीआईपी रोड–बड़े तालाब में मिला युवक का शव

भोपाल (नप्र)। भोपाल के वीआईपी रोड स्थित बड़े तालाब में रविवार दोपहर 3 बजे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों ने शव को पानी में तैरता देखा और तलैया थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

गोताखोर शेख आसिफ ने बताया कि शव को पानी से बाहर निकालने के बाद तलाशी ली गई। युवक की जींस की जेब से एक मोबाइल फोन और वाहन की

चाबी मिली। मोबाइल पानी में रहने के कारण खराब हो चुका है। मृतक के पैरों में चप्पल नहीं थी, जिससे प्रारंभिक तौर पर तालाब में छलांग लगाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस मौत के सही कारणों की जांच कर रही है।

24 घंटे पुराना है शव

पुलिस के अनुसार, मृतक की उम्र करीब 25 वर्ष है। उसने हल्के नीले रंग की जींस और धारीदार क्रीम रंग की शर्ट पहन रखी थी। शव करीब 24 घंटे पुराना प्रतीत हो रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक तालाब में कब और कैसे पहुंचा। तलैया थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

मुंबई में राज ठाकरे के घर में घुसा बंदरों का झुंड

- भगाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के मुंबई स्थित आवास पर रविवार को बंदरों का एक झुंड घर के परिसर में घुस आया। अचानक बंदरों के घुस जाने से अफरातफरी का माहौल बन गया। घर के अंदर बंदरों को देख परिवार और स्टाफ के लोग घबरा गए। इसके बाद तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम से संपर्क किया

और वन्यजीवों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए सहायता मांगी। मौके पर पहुंची टीम ने बंदरों को बिना किसी नुकसान के घर से बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बंदरों का झुंड घर के अलग-अलग हिस्सों में घूमता रहा जिससे कुछ समय के लिए वहां अफरातफरी का माहौल बन गया। हालांकि, इस घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने या किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। फिलहाल राज ठाकरे के घर पर बंदरों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने का अभियान जारी है। मुंबई जैसे महानगर में रिहायशी इलाकों में बंदरों के घुसने की घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं।

जम्मू कश्मीर में बादल फटे, 'प्रलय' की बारिश

11 लोगों की मौत, 2 साल के मासूम का शव निकाला

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ और किश्तवाड़ में शनिवार रात बादल फट गए। बाढ़-लैंडस्लाइड में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। पुंछ के सुरनकोट में लैंडस्लाइड से एक मकान मलबे में दब गया। उस वक्त घर में 8 लोग थे। इनमें 2 साल के बच्चे समेत 5 लोगों के शव बरामद किए गए। किश्तवाड़ के सुर्नू इलाके में बादल फटने से लोगों के घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा। राजौरी में भी भारी बारिश के बाद धारहाल नदी का जलस्तर बढ़ गया। करीब 200 से 250 गाड़ियां बह गईं। उत्तराखंड में शनिवार को लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा के रूट पर घोड़े- खच्चरों की सेवाएं रोक दी गईं।

मुख्यमंत्री ने अपना दौरा छोटा किया

इसी बीच, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की कि वह दिल्ली में अपना प्रवास छोटा कर रहे हैं और जमीनी स्थिति का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए जम्मू लौट रहे हैं। अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम चेतावनी और जम्मू डिवीजन के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हो रही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं आज दोपहर दिल्ली से जम्मू के लिए उड़ान भरूंगा, ताकि व्यक्तिगत रूप से जमीनी स्थिति का जायजा ले सकूं।

एलजी ने स्थिति की समीक्षा की

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारिश और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित पुंछ और राजौरी जिलों में स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिक प्रशासन, पुलिस, सेना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और स्थानीय स्वयंसेवकों की बचाव टीमें मौके पर काम कर रही हैं, जबकि सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त करते हुए सिन्हा ने पुंछ के हवेली और सुरनकोट इलाकों में हुई मौतों पर गहरा दुख जताया और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता का आश्वासन दिया।

एनएच -46 पर कार की बाइक में टक्कर, 3 की मौत

गुना में 7 साल के मासूम समेत माता–पिता ने दम तोड़ा; ग्वालियर की तरफ से आ रहे थे

गुना (नप्र)। गुना जिले के भदौरा क्षेत्र में नेशनल हाईवे-46 पर रविवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पति, पत्नी और उनके 7 वर्षीय बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

मृतकों की पहचान मनोज कुशवाह (34), उनकी पत्नी मालती कुशवाह (30) और बेटे कार्तिक (7) निवासी पिपरौदा के रूप में हुई है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने कार चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कार ग्वालियर से गुना तरफ आ रही थी। वहीं बाइक सवार भी गुना तरफ ही आ रहे थे। कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी है।

हाईवे पर हुआ भीषण हादसा

जानकारी के अनुसार, हादसा रविवार शाम करीब 4:45 बजे नेशनल हाईवे क्रमांक-46 पर भदौरा के पास हुआ। अर्टिगा कार ग्वालियर की ओर से गुना की तरफ आ रही थी, जबकि बाइक सवार परिवार गुना की ओर से ग्वालियर जा रहा था। इसी दौरान कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार मनोज कुशवाह, उनकी पत्नी मालती और 7 वर्षीय बेटे कार्तिक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

बंगाल में पुलिस की वर्दी में चोरी हुई, मेरा ऑफिस तोड़ा

अभिषेक बोले-बीजेपी के गुंडे सामान उठा ले गए, कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगाई

कोलकाता (एजेंसी)। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में पश्चिम बंगाल पुलिस खुद कानून तोड़ने वाली बन गई है। यह बयान उन्होंने दक्षिण 24 परगना के अमतला स्थित अपने ऑफिस को तोड़े जाने के एक दिन बाद दिया। शनिवार को जिला प्रशासन ने इमारत का अगला हिस्सा बुलडोजर से गिरा दिया था। आरोप था कि यह बिना मंजूरी के बना था। हालांकि रविवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने इस तोड़-फोड़ पर रोक लगा दी है। साथ ही इसे अगली सुनवाई तक ज्यों का त्यों रखने का आदेश

दिया है। इससे पहले इमारत तोड़ने के बाद रात का एक वीडियो अभिषेक ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। अभिषेक ने आरोप लगाया- बंगाल पुलिस बीजेपी के गुंडों के साथ मिलकर लैपटॉप, प्रिंटर, कागजात, टेबल, कुर्सियां और दूसरे फर्नीचर से भरे बक्से ले जा रही है।

राममंदिर चढ़ावा चोरी पर राहुल ने मोदी को लिखी चिट्ठी

कहा-आपकी चुप्पी स्वीकार नहीं, ट्रस्ट के खाते सार्वजनिक हों

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। खातों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि हर भक्त जान सके कि चढ़ावे का इस्तेमाल कहां और कैसे हुआ। जांच में जो भी जिम्मेदार पाए जाएं, उनकी जवाबदेही तय हो। शनिवार को लिखी चिट्ठी रविवार को सामने आई। उन्होंने पीएम मोदी से कहा-आपने संसद में ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, लेकिन इसके सदस्यों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार ने की। यह बात जगजाहिर है कि ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस, वीएचपी और उसके सहयोगियों से जुड़े हैं। पूर्व महासचिव भी आपके करीबी थे। ऐसे में आपकी चुप्पी स्वीकार नहीं है। जवाबदेही सुनिश्चित करना आपका कर्तव्य है। सरकार और ट्रस्ट की साख इसी बात पर टिकी है। इधर, आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके

भतीजे मनीष की पुलिस कस्टडी का आज आखिरी दिन है। शनिवार सुबह साढ़े 8 बजे पुलिस दोनों को जिला जेल से अपने साथ 39 घंटे की रिमांड पर ले गई थी। पुलिसकर्मी रात 11 बजे तक अपने ऑफिस में ही मौजूद रहे। आरोपियों को कहीं और नहीं ले जाया गया। टिन्नू, पूर्व महासचिव चंपत राय का करीबी रहा है। वह मंदिर के दानपात्रों की देखरेख करता था, जबकि मनीष चढ़ावे की गिनती का काम करता था।

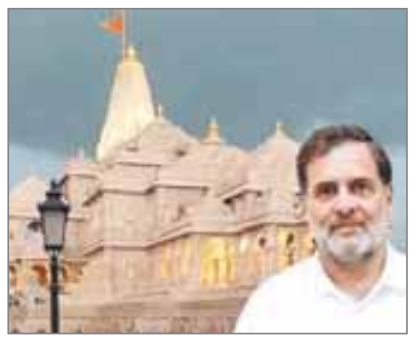

संघ और विहिप ने 23 जुलाई को संतों का सम्मेलन बुलाया

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 23 जुलाई को अयोध्या की मणिराम छावनी में संतों का सम्मेलन बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक, आरएसएस के स्वयंसेवक और वीएचपी के कार्यकर्ता श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। संभल में शनिवार को ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिममीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर हमला बोला।

ईरान में बड़ी तबाही मचाने की तैयारी,हालात बिगड़ने की चेतावनी

अरब देशों में अलर्ट पर 50 हजार अमेरिकी सैनिक

वॉशिंगटन (एजेंसी)। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया है कि शनिवार को अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार आठवीं रात बमबारी की है। इन हमलों में ईरान की निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाओं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल-ड्रोन स्टोरेज साइटों को निशाना बनाया गया। ये हमले ईरान के जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाने के बाद किए गए। जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और अमेरिका ने अपने सैनिकों को अलर्ट कर दिया है। अमेरिका की इस तैयारी से युद्ध के तेजी से बढ़ने और ईरान पर ज्यादा हमलों को अंदेशा बढ़ रहा है। इजरायली वेबसाइट यरुशलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यूएस सेंट्रल कमांड के हवाले से बताया है पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना पूरी तरह से

अलर्ट पर रखे गए है। पश्चिम एशिया में अमेरिका के 50,000 से अधिक सैनिक तैनात हैं। तनाव को देखते हुए सभी सैनिक अलर्ट मोड पर हैं और आगे की किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमेरिका अरब में सैनिकों के अलावा अपने फाइटर जेट की मौजूदगी बढ़ा रहा है। इसके लिए जर्मनी के स्पैंगडाहलेम एयर बेस से एफ-16 और ब्रिटेन से एफ-35 स्टील्थ फाइटर जेट भेजे जा रहे हैं। ये विमान इजरायल और दूसरे बेसों पर तैनात किए जाएंगे। अमेरिका से अतिरिक्त एरियल रिफ्यूलिंग (हवा में ईंधन भरने वाले) विमान भी इजरायल भेजे जा रहे हैं।

इजरायल की घटनाक्रम पर नजर

यरुशलम पोस्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर इजरायल बारीकी से नजर रख रहा है। अमेरिकी सेना लगातार आठ रातों के हमलों के बाद नौवें दिन भी ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि फिलहाल ईरान ने उनके देश पर हमले से परहेज किया है लेकिन आने वाले दिनों में चीजें किसी भी तरफ जा सकती हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने फिलहाल इजरायल से लड़ाई से दूर रहने के लिए कहा है। इजरायल ने कथित तौर पर ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल होने की पेशकश की थी लेकिन वॉशिंगटन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

दतिया उपचुनाव

जीतू पटवारी ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को लगाया गले, एक दिन पहले कहा था कि पहली बार सुना हूं नाम

दतिया (नप्र)। मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। दतिया से लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का सामान बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से हुआ है। जीतू पटवारी ने आशुतोष तिवारी को गले लगा लिया। इस दौरान दोनों मुस्कुराते नजर आए हैं।

आशुतोष तिवारी पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव- दरअसल, दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का पत्ता काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से आशुतोष तिवारी लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ही उनका सामना आशुतोष तिवारी से हुआ। इस दौरान जीतू पटवारी ने उन्हें मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। अब तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है।

मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा विधानसभा भवन का अवलोकन किया गया। फोटो : प्रवीण वाजपेई

बलराम कृषि महोत्सव-2026

कृषि महोत्सव : झाबुआ में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन किसानों से की चर्चा

प्रशासन पूरी तैयारी के साथ किसानों की सहायता के लिए तत्पर रहे

आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती और सिंचाई में विस्तार से बनेगा समृद्ध मध्यप्रदेश

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को झाबुआ में बलराम कृषि महोत्सव के अंतर्गत आनलाइन किसानों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने तथा आधुनिक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उल्लेखनीय है कि कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव-2026 मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर से इसकी शुरूआत की। अगला बलराम कृषि महोत्सव 21 जुलाई को आलीराजपुर में, 23 जुलाई को बड़वानी, 25 जुलाई को खरगौन में, 27 जुलाई को बुरहानपुर में और 30 जुलाई को खण्डवा में आयोजित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने झाबुआ में बलराम कृषि महोत्सव में कहा कि मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रशासन को पूरी तैयारी के साथ किसानों की सहायता के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि किसानों को तीन लाख रुपये तक का कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को मात्र पांच रुपये में बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं तथा डेयरी विकास के लिए 40 लाख रुपये तक की योजना में 33 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक सलाह, प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण के सिद्धांतों को अपनाकर कृषि को अधिक लाभकारी बनाएं। केंद्र एवं राज्य सरकार किसान हितों की रक्षा तथा कृषि विकास के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्राकृतिक खेती के विजन को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत झाबुआ जिले में 50 कृषि सखियों का चयन किया गया है। जिले में वर्तमान में लगभग 3,125 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है तथा किसानों की प्राकृतिक खेती का प्रमाणीकरण भी कराया गया है।

उन्होंने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद योजना के माध्यम से कड़कनाथ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 में जिले में कड़कनाथ पालन से एक हजार से अधिक नए हितग्राही जोड़े गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के साथ पशुपालन किसानों की नियमित आय का मजबूत आधार बन सकता है।

महोत्सव की गतिविधियां

बलराम कृषि महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीजों, नवीन कृषि यंत्रों, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण तथा शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है जिससे खेती अधिक लाभकारी, टिकाऊ एवं समृद्ध बन सके।

महोत्सव में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उत्कृष्ट किसानों का सम्मान भी किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरण, कृषि यंत्रों एवं उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन तथा किसानों को तकनीकी साहित्य भी उपलब्ध कराया जा रहा है। महोत्सव में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, कृषि अभियांत्रिकी तथा अन्य संबंधित विभागों द्वारा आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई है। किसानों को विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों से सीधे संवाद का और अपनी समस्याओं के समाधान किया जा रहा है। साथ ही उन्हें नवीन तकनीकों एवं बाजार आधारित कृषि मॉडल की जानकारी भी मिलेगी। किसानों को डिजिटल कृषि सेवाओं, ऑनलाइन कृषि परामर्श, मौसम आधारित खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सिंचाई, उन्नत कृषि यंत्रों तथा आधुनिक कृषि प्रबंधन प्रणालियों की जानकारी मिल रही है। किसानों को बदलती जलवायु के अनुरूप खेती की नई पद्धतियों एवं जोखिम प्रबंधन के उपायों से भी अवगत कराया जा रहा है।

13 नवम्बर तक होंगे आयोजन

कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, एमएसएमई, राजस्व, ऊर्जा सहित 16 विभागों को एक मंच पर लाकर किसानों के समग्र विकास का अभियान है। किसानों की आय बढ़ाने के लिये रोडमैप तैयार किया गया है। यह महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने, प्रसंस्करण, विपणन और रोजगार से जोड़ने का व्यापक अभियान है। प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 13 नवम्बर तक अनेक आयोजन होंगे और खेती-किसानी पर आधारित गतिविधियां आयोजित की जायेंगी।

6 प्रमुख कृषि संकल्प

बलराम कृषि महोत्सव में कृषि विभाग के साथ उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता, कृषि अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास तथा अन्य संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी है।

महोत्सव के माध्यम से किसानों को 6 प्रमुख कृषि संकल्पों से जोड़ा गया है -

- प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा।
- जल संरक्षण एवं हर खेत को पानी की दिशा में प्रयास।
- कृषि यंत्रीकरण एवं आधुनिक तकनीकों का विस्तार।
- फसल विविधीकरण एवं मूल्य संवर्धन।
- किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) तथा कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन।
- शासन की किसान कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ किसानों तक पहुंचाना।

झाबुआ का टमाटर बना प्रदेश की पहचान

मुख्यमंत्री ने पेटलावद में स्थापित टमाटर प्रसंस्करण इकाई का उल्लेख करते हुए कहा कि जिले में 2,812 हेक्टेयर क्षेत्र में टमाटर की खेती की जा रही है तथा लगभग 1.68 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। यहां टमाटर उत्पादक किसानों का क्लस्टर विकसित किया गया है तथा टमाटर सॉस और केचअप का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा 12 सोलर ड्रायर यूनिट स्थापित कर टमाटर का डिहाइड्रेशन भी किया जा रहा है। झाबुआ का टमाटर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना पूर्ण होने पर लगभग 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा तथा करीब 50 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। इससे जल संरक्षण, सिंचाई दक्षता एवं कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा कम पानी में अधिक उत्पादन संभव हो सकेगा।

मैं मंत्री हूं तो क्या सारा काम पतिदेव को सौंप दूं?

नपा अध्यक्ष के पति की बात पर लगे ठहाके तो मंत्री राधा सिंह ने दी नसीहत

मैहर (नप्र)। मध्य प्रदेश के नवनिर्मित मैहर जिले से एक बड़ा ही दिलचस्प और राजनीतिक गलियारों में चर्चा बटोरने वाला वाकया सामने आया है। जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने एक गरिमामयी मंच से हल्के-फुल्के अंदाज में पुरुष प्रधान मानसिकता पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पतियों द्वारा सत्ता और जिम्मेदारी संभालने की प्रथा पर दोटूक आपत्ति जताई।

पटेहरा (वार्ड क्रमांक-4) स्थित शासकीय प्राथमिक शाला परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह वाकया हुआ। प्रभारी मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जब सरकार कानून बनाकर महिलाओं को आगे ला रही है, तो उनके पति उन्हें पीछे धकेलने का काम बिल्कुल न करें।

परिचय के दौरान शुरू हुआ चुटीला संवाद- वाकया उस समय का है जब प्रभारी मंत्री राधा सिंह मंच पर मौजूद अतिथियों और जनप्रतिनिधियों का औपचारिक परिचय दे रही थीं। परिचय के दौरान उनकी नजर मैहर नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोनी के पति संतोष सोनी पर पड़ी। मंत्री ने उनकी तरफ इशारा करते हुए जैसे ही कहा, यहां उपस्थित नगर परिषद के... तभी बीच में टोकते हुए संतोष सोनी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ और बोल दीजिए। इतना सुनते ही मंच और पंडाल में बैठे लोग हंस पड़े। बात यहीं नहीं रुकी, मंत्री राधा सिंह ने भी मुस्कराते हुए पलटवार किया, क्योंकि हम अमूमन सरपंच के पति को क्या बोलते हैं (सरपंच पति)?

इस पर संतोष सोनी ने चुटकी लेते हुए कहा, आपको तो इसका पूरा अनुभव है। इस हाजिरजवाबी पर पूरा पंडाल एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा।

क्या मैं अपने पतिदेव को प्रभार सौंप दूं?- हंसी-मजाक के बीच प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने बेहद संजीदा और कड़ा संदेश दिया। उन्होंने संतोष सोनी की तरफ सीधे देखते हुए बड़ी बात कह दी।

सरकार तो महिलाओं को आगे लाना चाहती हैं, लेकिन आप लोग उन्हें फिर पीछे कर देते हैं। ये तो पूरी तरह गड़बड़ है। मिसाल के तौर पर, आज मैं मंत्री बनी हूं, तो क्या मैं अपने पतिदेव को इस प्रभार के जिले में भेज दूं? और उनसे कहूं कि जाओ भाई, प्रभारी मंत्री तो मैं हूं लेकिन सारा काम और जिम्मेदारी आप ही संभालो? ऐसा हमारी बहन के साथ बिल्कुल मत करिए। सरकार ने कानून बनाकर उन्हें घर की चौखट से बाहर निकाला है, नेतृत्व दिया है, तो उन्हें खुलकर काम करने देना चाहिए।

बिहार से लापता किशोरी भोपाल में मिली

युवक से जबरन शादी कराई गई, एक साल तक रेप करता रहा तथाकथित पति

भोपाल (नप्र)। भोपाल की शाहपुरा पुलिस ने एक 16 साल की किशोरी की शिकायत पर उसके कथित पति के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज की है।

पीड़िता का आरोप है कि एक साल तक उसे शाहपुरा की एक मल्टी में जबरन बंधक बनाकर रखा गया। यहीं आरोपी ने उसके साथ जबरन शादी की थी। उसे मारा-पीटा जाता और घरेलू काम कराया था। शादी करने वाला युवक उसके साथ कई बार संबंध बना चुका है। मौका मिलते ही वह आरोपी के चुंगल से छूटकर थाने पहुंची। पुलिस इस मामले में मानव तस्करी के एंगल पर भी जांच कर रही है। सीडब्ल्यूसी के समक्ष सोमवार को पीड़िता के बयानों को दर्ज कराया जाएगा।

एसआई हरीश ने बताया कि 16 वर्षीय पीड़िता 1 मार्च 2025 को सेरसा जिला बिहार से स्थित अपने घर से मां-पिता से नाराज होकर निकली थी। पुनिया जिला बिहार में ट्रेन में सफर के दौरान उसकी मुलाकात ट्रेन में दंपती से हुई। दोनों फुसला कर और सहारा देने के नाम पर उसे भोपाल ले आए। यहां दो दिन के भीतर जबरन उसकी शादी शाहपुरा की एक मल्टी में रहने वाले युवक से कराई गई। एक साल तक आरोपी उसके साथ संबंध बनाता रहा। युवक से विवाद के बाद वह शनिवार की रात को किसी तरह से थाने आई।

कैबिनेट से पहले एमपी में हटाए गए दो जिलों के एसपी, टीकमगढ़ और श्योपुर के एसपी बदले गए

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग भोपाल के जगदीशपुर में हो रही है। कैबिनेट की मीटिंग से पहले दो एसपी के तबादले हुए है। टीकमगढ़ और श्योपुर के एसपी को हटा दिया गया है। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि दोनों के खिलाफ कई शिकायतें थीं। सीएम मोहन यादव दो दिन पहले टीकमगढ़ दौरे पर गए थे।

तीन आईपीएस अफसरों का तबादला- एमपी कैबिनेट मीटिंग से पहले तीन आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोहर सिंह मंडलोई टीकमगढ़ के एसपी थे। उन्हें हटा

दिया गया है और पुलिस मुख्यालय भोपाल भेज दिया गया है। 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर कुमार अग्रवाल को टीकमगढ़ एसपी बनाया गया है। सुधीर कुमार अग्रवाल अभी श्योपुर के एसपी थे।

वहीं, 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी मोती उर रहमान को श्योपुर का नया एसपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि टीकमगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर टीकमगढ़ एसपी को लेकर सीएम के पास कई शिकायतें पहुंची थीं। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। भोपाल आने के बाद सीएम ने उन्हें पद से हटा दिया है।

गौरतलब है कि टीकमगढ़ एसपी के तबादले के बाद कई तरह की अटकलें हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है कि दोनों के ट्रांसफर क्यों हुए हैं। सीएम मोहन यादव का फील्ड में तैनात अधिकारियों के लिए क्लियर मैसेज रहा है कि फील्ड में रहना है तो परफॉर्म करना होगा। अब बदले गए आईपीएस अधिकारी जल्द ही नई जगहों पर जाकर कार्यभार संभालेंगे। इन तबादलों से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

छात्रा से रेप की कोशिश, जहर पिलाने का आरोप

देवास (नप्र)। देवास के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय 11वीं कक्षा की छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर घर में घुसकर छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास, मारपीट और जबरन जहरीला पदार्थ पिलाने का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

परिजनों के अनुसार, यह घटना शनिवार दोपहर करीब 1 बजे हुई, जब परिवार के सदस्य पूजा का सामान लेने बाहर गए थे। उनका आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस का 19 वर्षीय युवक घर में घुस आया।

आरोप है कि युवक ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। कुछ देर बाद जब परिजन घर लौटे, तो उन्होंने आरोपी को मौके से भागते हुए देखा। उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह फरार हो गया। गंभीर हालत में छात्रा को उज्जैन रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

शनिवार देर रात इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। रविवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। परिजनों का यह भी आरोप है कि करीब एक माह पहले भी उक्त युवक ने छात्रा से छेड़छाड़ की थी। उस समय परिवार ने उसे समझाइश दी थी और उसने माफी मांग ली थी।

जमीन नहीं, झोपड़ी में रहता है परिवार, पासबुक में बैलेंस देख फटी रह गईं आंखें

गरीब के बैंक खाते में 7 अरब 40 करोड़ 68 लाख रुपये

हरदा (नप्र)। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिस आदिवासी परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, परिवार झोपड़ी में रहकर गुजारा करता है। खेती के लिए जमीन नहीं है मजदूरी करके जीवन यापन करता है। उसके खातों में अरबों रुपये हैं। मामला सामने आने के बाद आसपास के लोग हैरान हैं।

दरअसल, मामला खिरकिया विकासखंड के देवपुर गांव का है। यहां रहने वाले आदिवासी समुदाय के गुलाब सिंह ठाकुर और उनकी भाभी का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता है। हाल ही में गुलाब सिंह का पोता दादा के साथ पेंशन और तेंदूपत्ता मजदूरी की राशि निकालने के लिए एक कियोस्क सेंटर गया था। यहां से उसने 500 रुपये निकाले। इस दौरान कियोस्क संचालक ने

बताया कि उसके खाते में करीब 7 अरब रुपये हैं।

पासबुक में बैलेंस देख हैरान हो गए- गुलाब सिंह के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते का बैलेंस 7,40,68,72,895 रुपये था। जब उसके पोते ने पासबुक का बैलेंस देखा तो उसके होश उड़ गए। अकाउंट में 7 अरब 40 करोड़ 68 लाख से अधिक रकम देखकर उसकी आंखें आंखें फटी रह गईं। खाते में इतना पैसा देख पोता घबरा गया और उसने मामले की जानकारी बैंक को दी।

झोपड़ी में रहता है परिवार

आदिवासी परिवार को खाते में इतने पैसे कहां से आए उन्हें कोई जानकारी नहीं है। परिवार ने बताया कि वह मजदूरी करने अपना जीवन चलाते हैं। उनके पास खेती करने के लिए खुद की जमीन भी नहीं है। डूब क्षेत्र से विस्थापित होकर गांव में रह रहे हैं। परिवार ने कहा कि उनका घर मजदूरी और सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ से चल रहा है।

चतुर्मास के लिए आचार्य समय सागर महाराज भोपाल पहुंचे

नारायण नगर मंदिर से निकली शोभायात्रा; महिलाएं, युवा, बच्चे सभी हुए शामिल

भोपाल (नप्र)। भोपाल में रविवार को जैन समाज की श्रद्धा और भक्ति में सराबोर नजर आई। चतुर्मास के लिए आचार्य समय सागर महाराज का 20 मुनियों के संघ के साथ भव्य मंगल प्रवेश हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनकी अगवानी के लिए पहुंचे और पूरे मार्ग पर जयकारे गूंजते रहे।

नारायण नगर जैन मंदिर से निकली शोभायात्रा- नारायण नगर जैन मंदिर से शुरू हुई शोभायात्रा में महिलाएं, युवा, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। श्रद्धालु आचार्य विद्यासागर महाराज की जय और आचार्य समय सागर महाराज की जय के जयकारे लगाते हुए पूरे मार्ग पर आचार्य संघ के साथ चलते रहे। शोभायात्रा में महिलाएं, युवा, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए।

मुनियों ने की चरण वंदना- प्रवक्ता अंशुल जैन ने बताया कि नाके चौराहे पर मुनि निर्णय सागर महाराज,

उपाध्याय विश्रुत सागर महाराज और निर्यापक मुनि संभव सागर महाराज सहित संघ ने आचार्य समय सागर महाराज की परिक्रमा कर चरण वंदना की। यह दृश्य श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा।

झांकियों ने दिया सेवा और जीव दया का संदेश- शोभायात्रा में जीव दया, गोसेवा और हथकरघा को बढ़ावा देने वाली आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। निर्माणाधीन रानी कमलापति जिनालय की प्रतिकृति भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। विभिन्न मंदिर समितियों, महिला मंडलों, युवा मंडलों, सोशल ग्रुप, पाठशाला परिवार और दिव्य घोष दल ने गुरु भक्ति से जुड़ी प्रस्तुतियां दीं।

दूसरे राज्यों से भी पहुंचे श्रद्धालु- अंशुल जैन के अनुसार भोपाल के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शहर के कई सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक संगठनों ने अलग-अलग स्थानों पर स्वागत मंच बनाकर आचार्य संघ का अभिनंदन किया।

धर्मसभा में आचार्य विद्यासागर को किया नमन

रानी कमलापति जिनालय पहुंचने पर भगवान आदिनाथ के दर्शन किए गए। इसके बाद धर्मसभा में श्रद्धालुओं ने श्रीफल अर्पित कर अष्टद्रव्य से आचार्य श्री के गुणों की वंदना की।

धर्मसभा को संबोधित करते हुए आचार्य समय सागर महाराज ने आचार्य विद्यासागर महाराज के दीक्षा दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर महाराज राष्ट्र निर्माण, संस्कृति संरक्षण और आत्मकल्याण के प्रेरणास्रोत हैं। उनके बताए आदर्श समाज को हमेशा सही दिशा देते रहेंगे।

संपादकीय

अंतरिक्ष में बड़ी कामयाबी!

निजी क्षेत्र में विकसित भारत का पहले ऑर्बिटल रॉकेट 'विक्रम-1' ने कई टेक्नोलॉजी डेमोनेस्ट्रेशन पेलोड और पोस्टकार्ड्स को लो अर्थ ऑर्बिट को स्थापित कर देश को नई उपलब्धि दिलाई है। इस सफलता से पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी है। 'विक्रम 1' अपने जो पोस्टकार्ड ले गया है, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट कार्ड भी है। निजी क्षेत्र का यह पहला राकेट निजी कंपनी हैदराबाद की स्काईरूट एयरोस्पेस कंपनी द्वारा निर्मित है, जिसे इसरो ने अपने लांच पैड से लांच किया। करीब चार साल पहले इसी कंपनी ने विक्रम-एस नामक एक सबऑर्बिटल रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। स्काईरूट एयरोस्पेस कंपनी के सह-संस्थापक पवन कुमार चंदना के अनुसार इस लांचिंग को 'मिशन आगमन' नाम दिया गया है। यह भारत का पहला कमर्शियल लॉन्च व्हीकल है। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम-1 रखा गया है। विक्रम-1 सैटेलाइट को 'लो अर्थ ऑर्बिट' में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह छोटे साइज के सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम है। दावा है कि यह सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इस रॉकेट का वजन 40 टन है और यह 20 मीटर यानी लगभग सात मंज़िला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। इसकी क्षमता 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सैटेलाइट ले जाने की है। विक्रम-1 के जरिए छह तरह के पेलोड चांद पर भेजे जा रहे हैं। स्काईरूट ने घोषणा की है कि विक्रम-1 के लॉन्च के बाद विक्रम-2 का लॉन्च किया जाएगा। इसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। विक्रम-1 की तरह ही इसमें कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर होगा और एडवांस क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने 2019 में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथोराइजेशन सेंटर (इन-स्पेस) की स्थापना के साथ स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था। यह संस्था प्राइवेट सेक्टर और इसरो जैसी सरकारी एजेंसियों के बीच एक सिंगल-विंडो इंटरफेस के रूप में काम करती है। विक्रम 1 की कामयाब लॉचिंग के बाद निजी क्षेत्र में उपग्रहों को लांच करने का नया क्षेत्र खुलेगा। इससे इसरो को भी आय होगी, क्योंकि लांचिंग पैड उसी के पास हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस सफल लांचिंग के बाद भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक नए और महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गया है। एक तरफ अंतरिक्ष में हमारे निजी स्टार्ट अप की यह सफलता है तो दूसरी तरफ चिंता की बात 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' यानी इसरो से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का तेजी से नौकरी छोड़ना है। हालांकि सरकार ने एक आदेश जारी कर वैज्ञानिकों के इस्तीफे मंजूर करने पर रोक लगा दी है, लेकिन यह दबाव बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। क्योंकि नौकरी छोड़ने के इच्छुक वैज्ञानिकों को जबरन रोका गया तो उनके मन में कुंठा और निराशा फैल सकती है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के इसरो छोड़ने के पीछे कारण निजी स्टार्ट अप्स में बेहतर वेतन और काम करने के अवसर हैं। बताया जाता है कि पिछले एक साल में अनुमानित 100-120 वैज्ञानिक इसरो छोड़कर स्पेस स्टार्टअप्स से जुड़ गए हैं, जहां वह मनमाना काम कर सकते हैं। इसरो भी कितना ही बड़ा और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान क्यों न हो, लेकिन कामकाज की सरकारी रफ्तार से वह भी अछूता नहीं है। लिहाजा सरकार को भी अपनी वैज्ञानिकों की सेवा शर्तों और प्रतिभा उपयोग के अपने पारंपरिक मानदंडों पर पुनर्विचार करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। अन्यथा इसरो जैसी देश की गौरवपूर्ण संस्था प्रतिभाओं से खाली होने में देर नहीं लगेगी। ऐसा हुआ तो यह राष्ट्रीय हानि होगी। यह कहीं से भी देशहित में नहीं होगा।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

चिकित्सा मूल अधिकार बने

यद्यपि दुनिया में चिकित्सा के क्षेत्र में नये-नये प्रकार की खोजें हुई और प्रतिदिन हो रही हैं। ऐसी बीमारियां जो सदियों से लाइलाज मानी जाती थीं, उनका भी इलाज और दवाइयाँ खोजी गई। 17-18 वीं सदी में प्रतिवर्ष लाखों लोग देश में हैजा, टीबी जैसी बीमारियों से मौत के शिकार होते थे, परंतु अब इनसे होने वाली मौतें बहुत कम हो गयी। 19वीं सदी में देश में हैजा से मरने वालों की संख्या लाखों में थी परंतु अब इनकी वैक्सीन के आने से इनसे होने वाली बीमारियों से मृत्युदर भी कम हुई। हालांकि दूसरी तरफ कैंसर जैसी नयी-नयी बीमारियों का उदय हुआ है जिससे मरने वालों की संख्या काफी बढ़ी है। कैंसर का फैलाव भी पिछले दो दशकों में काफी हुआ है। और लाखों लोग कैंसर के शिकार हैं। कैंसर के इस फैलाव की वजह पर कुछ कह पाना निश्चित नहीं है। परंतु विशेषज्ञों का कहना है कि देश में बढ़ता प्रदूषण, धूल और धुआँ, पानी, वायु और खाद्यान्न में दवाईयों के नाम पर घुलता जहर इसका बड़ा कारण है। पिछले तीन चार दशकों में देश में बड़े-बड़े अस्पताल खुले हैं। फाइव स्टार संस्कृति के निजी अस्पतालों का भी भारी फैलाव हुआ है, परंतु देश का आम आदमी अभी भी चिकित्सा के अभाव में जी रहा है। भारत सरकार ने आयुष्मान योजना बनाई परंतु उसमें केवल बड़ी बीमारियां ही शामिल की गई और इसका लाभ सामान्य व्यक्तियों और आमजन के लिये यह योजना सरकारों के संरक्षण में भ्रष्टाचार का शिकार हो गयी। पिछले दिनों यह खबर अखबारों में आयी थी कि सैकड़ों करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार आयुष्मान योजना में हुआ है। बहुतेरे अस्पतालों के संदिग्ध बिल सरकारों ने रोक दिये और अब स्थिति यह है कि अधिकांश अस्पताल आयुष्मान कार्ड मानने को तैयार नहीं हैं।

देश में लगभग 8-10 करोड़ लोग जिनमें केंद्र और राज्य के अधिकारी, कर्मचारी, सांसद, विधायक, निजी कंपनियों के कर्मचारी, व्यापार में संलग्न लोग आदि शामिल हैं। जिनके पास किसी न किसी प्रकार का चिकित्सा बीमा है या सरकार के स्तर से चिकित्सा की सुविधायें हैं। जो अति गरीब लोग हैं उन्हें भी सरकार की ओर से इलाज मुफ्त मिलता है यद्यपि वह सामान्य बीमारियो तक ही ज्यादा होता है। परंतु देश का एक निम्न और सामान्य मध्यवर्ग जिसमें छोटे किसान, छोटे कर्मचारी, छोटे व्यापारी जैसे लोग हैं और जिनकी संख्या 60 करोड़ से कम नहीं होगी, ये लोग आज भी छोटी या बड़ी बीमारी के इलाज के लिए सरकार की सूची से बाहर हैं। इनमें बीमा कराने की क्षमता भी नहीं है, कोई गंभीर बीमारी के आने पर अपनी अचल संपत्ति को बेचकर या कर्ज लेकर इलाज कराने को लाचार हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने पिछले लगभग 3 दशकों से यह मांग की है, (धरना, प्रदर्शन, सभा ज्ञापन आदि के माध्यम से) तथा भारत सरकार से अनुरोध किया है कि चिकित्सा को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए ताकि सभी को जरूरत के अनुसार चिकित्सा और दवा उपलब्ध हो सके तथा

चिकित्सा क्षेत्र का निजीकरण समाप्त कर समाजीकरण करना चाहिए। चिकित्सा और शिक्षा देना किसी भी सरकार का मौलिक और संवैधानिक दायित्व है। जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनीं थीं तब उन्होंने हमारे ज्ञापन को गंभीरता से लेकर पहल शुरू की थी। बात काफी आगे तक बढ़ी भी परंतु उनका समय समाप्त होने के बाद यह प्रस्ताव फाइलों में बंद होकर मौत का शिकार हो गया।

अब देश में जो बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हैं निसंदेह पिछले 2 दशकों में उनकी संख्या बढ़ी है, पिछले 12 वर्षों में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या भी काफी बढ़ी है, परंतु इसमें दो प्रकार की समस्यायें हैंरू-

1. अब जो नये चिकित्सा महाविद्यालय पिछले 4-5 वर्षों में खोले जा रहे हैं वे सब पीपीपी मॉडल जिसका वास्तविक अर्थ प्रछन्न निजीकरण होता है, के आधार पर खोले जा रहे हैं और इनमें सामान्य व्यक्तियों के लिए इलाज कराना लगभग असंभव जैसा होता है। इनका लाभ भी संपन्न और बड़े लोग ही ले पाते हैं। गरीब तबका तो इससे वंचित ही रह जाता है। जाहिर सी बात है कि जब कोई पूंजीपति अपना पैसा किसी क्षेत्र में लगायेगा वह घोषित या अघोषित रूप से मुनाफे के लिए ही लगायेगा और उससे आमजन को लाभ नहीं होगा।

2. जो सरकारी अस्पताल हैं, उनकी संख्या अवश्य बढ़ी है परंतु, क्या वह बढ़ी हुई आबादी की तुलना में पर्याप्त हैं? इस पर विचार करना चाहिए। देश की आबादी बढ़कर अब 150 करोड़ के आसपास है और आज भी देश की राजधानी में जो सरकारी सबसे बड़ा अस्पताल जिसे एम्स कहा जाता है, की चिकित्सा की क्षमता क्या है? आपरेशनों के लिए 4-4, 5-5 साल का समय दिया जा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि गरीब का नंबर एम्स में नहीं लग पाता और यमराज के यहां लग जाता है।

अभी हमारे एक परिचित जो किसी व्यक्ति को जलने से बचाने के उपक्रम (प्रयास) में स्वतः जल गये थे, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में बर्न यूनिट में एयरलिफ्ट कर लाये गये थे। स्थिति यह थी कि उन्हें भर्ती करने के लिये बिस्तर भी खाली नहीं था और कुछ विशिष्ट प्रयासों के बाद उन्हें एक बेड मिल सका और जनरल वार्ड में भर्ती हो सके। उसमें अस्पताल के प्रबंधन या चिकित्सकों की कोई गलती नहीं है क्योंकि प्रतिदिन देशभर में जलने वाले मरीजों की संख्या सैकड़ों में है और उनके बर्न यूनिट की संख्या मुश्किल से 100 के आसपास है। यही स्थिति राजधानी के अन्य सरकारी अस्पतालों की है। जब दिल्ली में एम्स शुरू हुआ था तब दिल्ली शहर की आबादी 40 लाख और देश की आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। यही स्थिति राज्यों के एम्स (सिम्स) और सरकारी चिकित्सालयों की है। परंतु सरकार की नीतियों में आबादी नियंत्रण नहीं है बल्कि अब तो आबादी बढ़ाना है। आबादी बढ़ाने के अनेकों प्रयास सरकारें कर रही हैं, तीसरे चौथे बच्चों के जन्म लेने पर कुछ प्रोत्साहन राशि स्वरूप देना तथा महिला के साथ-साथ पुरुष को भी बच्चे पालने का अवकाश आदि सुविधाओं की घोषणा हो रही है परंतु, चिकित्सालयों में आबादी और जरूरत के अनुसार सुविधायें बढ़ाना भी सरकार की नीति नहीं है। एम्स में सांसदों, विधायकों, अफसरशाहों के लिए पृथक व्यवस्था है और इन्हें तत्काल जरूरत के अनुसार पर्याप्त आवश्यक इलाज मिल जाता है। सेना के लिए सैनिक अस्पताल हैं। कई अन्य सरकारी विभागों के अपने अपने अस्पताल हैं या उनके बड़े अस्पतालों से अपने कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए समझौते हैं। पब्लिक सेक्टर में अधिकांश ने अपने कर्मचारियों के लिए बढ़िया अस्पताल सरकारी धन से बनाये हैं परंतु देश के आम आदमी के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। जनप्रतिधियों की प्राथमिकतायें भी अब आम आदमी नहीं हैं बल्कि संसद और विधानसभाओं का अधिकांश समय गैर जरूरी मुददों और बहस पर जाता है। मेरे पढ़ने में कम से कम पिछले 3-4 दशकों में यह कभी नहीं आया कि किन्हीं सांसद महोदय ने लोकसभा में देश के इन आम और गरीबों की बात को उठाया हो। किसी ने पूछा हो कि देश के आम आदमी के लिए एम्स में 5-7 साल की तारीख ऑपरेशन के लिए क्यों दी जाती है? किसी ने पूछा हो कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक बिस्तर पर 2-2 मरीज क्यों हैं? मरीज को ले जाने वाली ट्रालियों पर 5-5 मरीज क्यों ले जा रहे हैं। इंसान यानि मरीज और उसके परिजन अस्पतालों में और उसके बाहर खुले मैदानों में रातभर जानवरों के समान पड़े रहते हैं। इन बड़े चिकित्सालयों में मरीजों के परिजनों के लिए कमरा तो दूर एक दरी बिछाकर सोने लायक जगह भी योजनाओं में नहीं है।

हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि-

1. चिकित्सा का मूल अधिकार बनाया जाये और सारी चिकित्सा सरकारी हो।
2. व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार चिकित्सा और दवायें उपलब्ध हों।
3. आबादी के नियंत्रण के लिए कार्यवाही हो।
4. बढ़ती आबादी और उसकी जरूरतों के अनुसार चिकित्सालयों की क्षमता बढ़ाई जाये।
5. सरकारी चिकित्सालयों की निर्माण योजना में मरीजों के परिजनों के लिए चिकित्सालय के प्रांगण में विश्रामस्थल बनाना अनिवार्य हो।

दृष्टिकोण

निलेश देसाई

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

असहमति से नफ़रत तक: लोकतंत्र की नैतिक परीक्षा

विश्व इतिहास का शायद सबसे बड़ा अहिंसक जनांदोलन था। गांधी ने यह स्थापित किया कि जनता की नैतिक शक्ति किसी भी साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति से बड़ी हो सकती है। स्वतंत्रता के बाद भी इसी परंपरा ने भूदान आंदोलन, चिपको, सूचना के अधिकार, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जनलोकपाल आंदोलन और अनेक स्थानीय जनसंघर्षों को दिशा दी। इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया; बल्कि उसे अधिक उत्तरदायी बनाया। इतिहास यह भी बताता है कि सत्ता और जनआंदोलनों के बीच तनाव हमेशा रहा है। औपनिवेशिक शासन ने गांधी और लोकमान्य तिलक पर देशद्रोह के मुकदमे चलाए। स्वतंत्र भारत में भी अलग-अलग विचारधाराओं की सरकारों ने विभिन्न आंदोलनों को संदेह की दृष्टि से देखा। इसलिए यह प्रश्न किसी एक दल या एक सरकार तक सीमित नहीं है।

गांधी, लोकतंत्र और हमारे समय का सबसे कठिन प्रश्न महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को कभी आंदोलन की तकनीक नहीं माना। उनके लिए सत्याग्रह सत्य की खोज, आत्मबल की अभिव्यक्ति और लोकतंत्र की नैतिक चेतना को जागृत करने का माध्यम था। वे कहते थे कि जब कोई व्यक्ति बिना घृणा, बिना हिंसा और बिना प्रतिशोध के अन्याय का सामना करते हुए स्वयं कष्ट सहता है, तो वह केवल शासक से नहीं, बल्कि पूरे समाज की अंतरात्मा से संवाद करता है। सत्याग्रह का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को पराजित करना नहीं, बल्कि उसके भीतर सोई हुई नैतिक संवेदना को जगाना है।

यही कारण है कि सत्याग्रह केवल सत्याग्रही के साहस पर निर्भर नहीं करता। उसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि समाज, मीडिया और शासन उस पीड़ा को देखने, समझने और उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं या नहीं। यदि सुनने की यह क्षमता कमजोर पड़ जाए, तो सत्याग्रह का नैतिक प्रभाव भी क्षीण होने लगता है।

आज भारत के लोकतंत्र के सामने यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा है। हाल के वर्षों में शिक्षा, पर्यावरण, कृषि, रोजगार, भूमि अधिकार और क्षेत्रीय स्वायत्तता जैसे अनेक मुद्दों पर शांतिपूर्ण धरने, पदयात्राएँ और अनशन हुए हैं। इनमें से कुछ को व्यापक समर्थन मिला, कुछ को सीमित ध्यान मिला और कुछ लगभग सार्वजनिक विमर्श से बाहर रह गए। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि कौन-सा आंदोलन सफल हुआ और कौन-सा नहीं; बल्कि यह है कि क्या आज भी अहिंसक प्रतिरोध लोकतांत्रिक निर्णय-प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है?

यह प्रश्न केवल किसी एक आंदोलन या सरकार का नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का प्रश्न है।

भारत का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास का शायद सबसे बड़ा अहिंसक जनांदोलन था। गांधी ने यह स्थापित किया कि जनता की नैतिक शक्ति किसी भी साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति से बड़ी हो सकती है। स्वतंत्रता के बाद भी इसी परंपरा ने भूदान आंदोलन, चिपको, सूचना के अधिकार, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जनलोकपाल आंदोलन और अनेक स्थानीय जनसंघर्षों को दिशा दी। इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया; बल्कि उसे अधिक उत्तरदायी बनाया।

इतिहास यह भी बताता है कि सत्ता और जनआंदोलनों के बीच तनाव हमेशा रहा है। औपनिवेशिक शासन ने गांधी और लोकमान्य तिलक पर देशद्रोह के मुकदमे चलाए। स्वतंत्र भारत में भी अलग-अलग विचारधाराओं की सरकारों ने विभिन्न आंदोलनों को संदेह की दृष्टि से देखा। इसलिए यह प्रश्न किसी एक दल या एक सरकार तक सीमित नहीं है। यह उस लोकतांत्रिक संस्कृति का प्रश्न है जिसमें असहमति को सम्मानपूर्वक सुनना धीरे-धीरे कठिन होता जा रहा है।

डिजिटल युग ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। आज सूचना पहले पहुँचती है और समझ बाद में बनती है। सोशल मीडिया ने नागरिकों को अभिव्यक्ति का अभूतपूर्व अवसर दिया है, लेकिन उसी के साथ समाज वैचारिक खेमों में भी बँट गया है। किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन उसके तर्कों से पहले उसकी राजनीतिक पहचान के आधार पर होने लगता है। परिणामस्वरूप संवाद सिकुड़ता है और आरोप-प्रत्यारोप उसका स्थान ले लेते हैं।

लोकतंत्र में असहमति होना स्वाभाविक है। हर आंदोलन सही हो, यह आवश्यक नहीं। हर मांग स्वीकार हो, यह भी संभव नहीं। लेकिन किसी भी लोकतंत्र की परिपक्वता इस बात से मापी जाती है कि वह असहमति का उत्तर किस प्रकार देता है। क्या वह संवाद करता है? क्या वह तथ्यों के आधार पर बहस करता है? या फिर वह विरोध करने वाले की नीयत पर ही प्रश्नचिह्न लगा देता है?

गांधी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा। उन्होंने यह विश्वास पैदा किया कि बिना हिंसा के भी अन्याय का प्रतिरोध किया जा सकता है और परिवर्तन संभव है। यदि यह विश्वास कमजोर पड़ने लगे कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध का कोई अर्थ नहीं रह गया है, तो इसका असर केवल आंदोलनों पर नहीं पड़ेगा; यह लोकतंत्र की बुनियाद को प्रभावित करेगा।

ऐसी स्थिति में समाज सामान्यतः तीन दिशाओं में बढ़ता है। पहली दिशा है उग्रता। जब लोगों को लगता है कि शांतिपूर्ण मार्ग से कुछ नहीं बदलता, तब कुछ लोग हिंसक या कट्टर रास्तों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं।

दूसरी दिशा है उदासीनता। लोग यह मान लेते हैं कि उनकी आवाज़ का कोई महत्व नहीं है। वे सार्वजनिक जीवन से दूरी बना लेते हैं। यह मौन लोकतंत्र के लिए उतना ही खतरनाक है जितनी हिंसा, क्योंकि इससे जवाबदेही की संस्कृति कमजोर होती है।

तीसरी दिशा आशा की है। प्रत्येक पीढ़ी अपने समय के अनुरूप प्रतिरोध के नए माध्यम खोजती है। गांधी के समय चरखा, नमक यात्रा और पदयात्राएँ प्रतीक बने थे। आज डिजिटल अभियान, नागरिक नेटवर्क, सामुदायिक संवाद, जनसुनवाई और सोशल मीडिया नए माध्यम बन रहे हैं। अहिंसा समाप्त नहीं होती; वह अपने स्वरूप बदलती है। किंतु उसका नैतिक आधार वही रहता है-सत्य, आत्मानुशासन और संवाद।

यहीं लोकतंत्र की असली परीक्षा आरंभ होती है।

क्या हमारी संसद, हमारी सरकारें, हमारा मीडिया और हमारा नागरिक समाज ऐसी आवाज़ों को सुनने की संवेदनशीलता बनाए रख पाए हैं? क्या हम असहमति को लोकतंत्र का स्वाभाविक अंग मानते हैं या उसे संकट के रूप में देखने लगे हैं?

सत्याग्रह का अर्थ केवल विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नैतिक परीक्षा भी है। जब कोई नागरिक बिना हिंसा के अपनी पीड़ा लेकर समाज और सत्ता के सामने बैठता है, तब केवल सरकार ही नहीं, पूरा समाज परीक्षा में होता है। प्रश्न यह नहीं कि हम उस आंदोलन से सहमत हैं या असहमत। प्रश्न यह है कि क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। लोकतंत्र केवल मतदान से नहीं चलता। वह विश्वास से चलता है। वह संवाद से चलता है। वह इस भरोसे से चलता है कि यदि कोई नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखेगा, तो उसकी बात सुनी जाएगी। यदि यह भरोसा टूटता है, तो सबसे बड़ी हार किसी आंदोलन की नहीं होती; लोकतंत्र की होती है।

दुर्भाग्य से आज असहमति को विचारों के मतभेद के रूप में नहीं, बल्कि विरोधी के प्रति नफ़रत के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। असहमति से नफ़रत का यह दौर लोकतंत्र की जड़ों को हिला रहा है। लोकतंत्र वहीं जीवित रहता है जहाँ विचारों का संघर्ष होता है, व्यक्तियों का नहीं। आज आवश्यकता केवल गांधी को याद करने की नहीं है, बल्कि उनके उस नैतिक आग्रह को पुनर्जीवित करने की है जिसमें विरोधी भी शत्रु नहीं, संवाद का सहभागी होता है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी आर्थिक वृद्धि या सैन्य क्षमता से नहीं, बल्कि अपनी आलोचना को सुनने, असहमति का सम्मान करने और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को सुधारने की क्षमता से मापी जाती है। सत्याग्रह इसलिए अतीत की विरासत भर नहीं है। वह भविष्य के लोकतंत्र की भी अनिवार्य शर्त है।

प्रश्न यह नहीं कि सत्याग्रह जीवित है या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या हमारी संवेदनाएँ अब भी उसे सुनने के लिए जीवित हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

मुकेश नेमा

लेखक मप्र के प्रशासनिक अधिकारी हैं।

मजे की बात है कि शरीफों की इकलौती पूंजी भी चुरा ली गई

होनहार चोर शिवपुरी के नरवर किले से मात्र तीन हज़ार किलो की अष्टधातु से बनी ऐतिहासिक तोप उतनी ही आसानी से चुरा ले गए हैं जैसे एक जमाने में साइकिलें चोरी हुआ करती थी। ये चोर काबिल और साहसी है। दक्ष योजनाकार है। जाहिर है उनका भविष्य उज्जवल है,कल के दिन वो खुद तोप होंगे, काम के हो सकते है,ऐसे में मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ।

आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि आज से पच्चीस-पचास साल पहले के लोग चोर होने में,चोर कहलाने में शर्माते थे। पर ऐसा भी नहीं उस दौर में चोर नहीं होते थे। खूब होते थे। पर पता नहीं क्यों ये वहम था उन्हें कि चोरी अच्छा काम नही है। मजबूरी में चोर बनते थे और चोरी करने से ज्यादा ताकत इस बात पर खर्च करते थे कि पकड़े न जाए और किसी को उनका चोर होना पता न चल जाए।

तब के जमाने में चोरी हो जाने पर लोग ऐसे हक्का बक्का होते थे जैसे भूत देख लिया हो। ऐसे बर्ताव करते थे जैसे खुद राजा हरीशचंद्र हो। ऐसे पेश आते थे जैसे कभी पडोसी का अखबार भी न उठाया हो उन्होंने। किसी और के यहाँ चोरी होने को मनोरंजन की तरह लिया जाता था। लोग बस चोर की,उसकी दिलेरी और चोरी करने के तरीके की,चोरी गए माल की और जिसके यहाँ चोरी हुई है उसकी बदक़िस्मती की चर्चा करते थे और तब तक करते थे जब तक अगली चोरी की खबर न आ जाए।

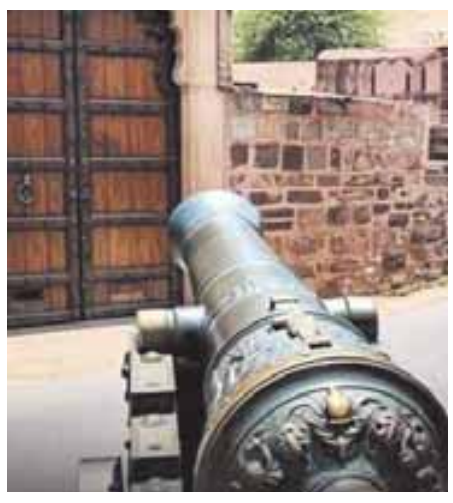

उन दिनों चोरी कोई ज्यादा फायदे का धंधा था भी नही। किसी के यहाँ सेंध लगाने की कड़ी मेहनत के बाद चोरी करने वाले के हाथ लगता क्या था? आमतौर पर कुछ गहने पैसे बरतन बस। वो इतनी छोटी सी चीजों के लिए अपनी जान जोखिम में डालता था। पकड़े जाने पर पिटता था, पुलिस के हाथों अपनी जमा पूंजी गँवाता था ओर जेल जाता था। कहने का आशय यह कि पुराने जमाने में चोर होना खुद को खतरे मे डालने जैसा था। चोर नाम और दाम दोनों से हाथ धो बैठता था पर शुक्र है अब ऐसा नहीं है।

एक सुखद बदलाव आ चुका हमारे यहां। चोरी के आयाम अब व्यापक हो चुके। धर्म राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी व्यापार ज़िंदगी का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ चोरी करने की गुंजाइश न हो। लोग समझ गए है कि चोर होने में नुकसान जैसा कुछ नहीं। इसमें धन है,रोमांच है, शोहरत है और सेल्फ कॉन्फ़िडेंस है। शरीफों के पास कभी इज़्ज़त ही हुआ करती थी। उसी को ओढ़ता बिछाता था वो। उस की ही नुमाइश करता था और फूला फूला फिरता था। मजे की बात शरीफों की ये इकलौती पूंजी भी उससे चुरा ली गई है।

अब इज्जत चोरों की होती है। और चोरों की ही होती है। चोर इतने इज्जतदार है कि चोर और सेठ मे भेद मिट चुका। हर बड़ा सेठ बस एक कामयाब चोर है। मजे की बात यह कि ये बात सभी को पता है,सभी को मंजूर है। सब सेठ हो जाना चाहते है। सभी को पता है कि चोर हुए बिना सेठ बना ही नहीं जा सकता , ऐसे मे अब सभी लोग चोर होने के लिए तड़पते है। और चोर होने को बुरा मानने वाले बेवकूफ माने जाते है।

जमाना चोरों का है,सारा जमाना चोर है। चोर होने पर गौरवान्वित है,पर अचरज की बात यह भी कि अब भी कुछ लकीर के फकीर बचे हुए है,डटे हुए है चोर न होने पर। बड़बड़ाते रहते है कि चोरी बुरा काम है। पर अब कोई नहीं पूछता उन्हें। अजीब माना जाता है ऐसे लोगों को। वो अनसुने किए जाते है और उनकी हँसी उड़ाई जाती है। जाहिर है ऐसे लोगों की किस्मत में फकीर बने रहना और फकीर होकर ही मर जाना लिखा है और इसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार हैं।

अब चारों तरफ चोर है और चोर होना ही मुख्य धारा है। यदि आप दूसरों को शरीफ़ लगते है,वाकई शरीफ हैं भी तो आप यकीनन गलत रास्ते पर है,और आपको पहली फुरसत मे चोर होकर यह गलती सुधार लेना चाहिए।

लैंगिक हिंसा बनाम सभ्य समाज: जहां हर कोई एक जैसा हो

कभी तो लगता है कि महिलाओं के विरुद्ध हुई हिंसा को हिंसा या अपराध की श्रेणी में गिना ही नहीं जाता है इसे उनकी नियति मानकर सामान्य घटना के रूप में देखा जाता रहा है। यही कारण है कि आदिम समाज से लेकर आज के आधुनिक सभ्य समाज तक इन घटनाओं पर कानून तो बहुत बने लेकिन लगाम नहीं लगा सके। आखिर क्यों, यानी कानून बना देने से ही सुधार संभव नहीं होता तो फिर क्या करना चाहिए इस पर सभी क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों को विचार करना होगा। बलात्कार की घटनाओं पर विभिन्न नारीवादी विचारकों ने अपना पक्ष रखते हुए माना है कि इसे मात्र एक व्यक्तिगत यौन इच्छा या वासना का अपराध नहीं माना जाना चाहिए। वे इसे पितृसत्ता, लैंगिक असमानता और महिलाओं पर पुरुष वर्चस्व बनाए रखने के एक हथियार के रूप में देखते हैं। नारीवादी कैथरीन मैककिनन का मानना है कि बलात्कार पुरुष शक्ति और प्रभुत्व का एक चरम रूप है। इसके जरिए महिलाओं को डराकर और नियंत्रित करके रखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज अक्सर बलात्कार के लिए पीड़िता के पहनावे, रहन-सहन या आचरण को दोषी ठहराता है। इस 'विक्टिम-ब्लेमिंग' (पीड़िता पर दोष मढ़ना) की प्रक्रिया के माध्यम से पितृसत्तात्मक समाज अपराधी को बचाने और महिलाओं को प्रताड़ित करने की व्यवस्था का समर्थन करता आया है।

विचार

डॉ. ज्योति सिडाना

लेखक स्तंभकार हैं।

आज के तकनीक निर्देशित समाज में लगभग सभी सामाजिक संबंध बेमानी से लगने लगे हैं, तकनीक ने मानव जीवन को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है संभवतः इसलिए सम्बन्ध कितने भी निकट के क्यों न हों उन पर विश्वास समाप्त हो गया है या कहें कि तकनीक के क्षेत्र में उत्पन्न क्रांति ने सामाजिक सम्बन्धों के समक्ष विश्वास का संकट पैदा कर दिया है। इस दौर में नवजात बच्चियों और किशोरियों के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटनाएं जितनी तेजी से बढ़ रही हैं पहले कभी देखी या सुनी नहीं गयी होंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं होती आई हैं लेकिन 4 दिन और 4 माह की बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं में वृद्धि इस सभ्य कहे जाने वाले समाज के मुहं पर तमाचा है परन्तु अफ़सोस यह है कि इस तमाचे की गूंज किसी को सुनाई नहीं दे रही।

कभी तो लगता है कि महिलाओं के विरुद्ध हुई हिंसा को हिंसा या अपराध की श्रेणी में गिना ही नहीं जाता है इसे उनकी नियति मानकर सामान्य घटना के रूप में देखा जाता रहा है। यही कारण है कि आदिम समाज से लेकर आज के आधुनिक सभ्य समाज तक इन घटनाओं पर कानून तो बहुत बने लेकिन लगाम नहीं लगा सके। आखिर क्यों, यानी कानून बना देने से ही सुधार संभव नहीं होता तो फिर क्या करना चाहिए इस पर सभी क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों को विचार करना होगा। बलात्कार की घटनाओं पर विभिन्न नारीवादी विचारकों ने अपना पक्ष रखते हुए माना है कि इसे मात्र एक व्यक्तिगत यौन इच्छा या वासना का अपराध नहीं माना जाना चाहिए। वे इसे पितृसत्ता, लैंगिक असमानता और महिलाओं पर पुरुष वर्चस्व बनाए रखने के एक हथियार के रूप में देखते हैं। नारीवादी कैथरीन मैककिनन का मानना है कि बलात्कार पुरुष शक्ति और प्रभुत्व का एक चरम रूप है। इसके जरिए महिलाओं को डराकर और नियंत्रित करके रखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज अक्सर बलात्कार के लिए पीड़िता के पहनावे, रहन-सहन या आचरण को दोषी ठहराता है। इस 'विक्टिम-ब्लेमिंग' (पीड़िता पर दोष मढ़ना) की प्रक्रिया के माध्यम से पितृसत्तात्मक समाज अपराधी को बचाने और महिलाओं को प्रताड़ित करने की व्यवस्था का समर्थन करता आया है।

हाल ही की कुछ घटनाओं में राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर 5 दिन तक 32 लोगों ने गैंगरेप किया। पश्चिम बंगाल के बूरुईपुरा में 12 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी, उत्तर प्रदेश के बरेली में 11 साल और हरदोई में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी और राजस्थान के जोधपुर में 4 माह की नवजात को भी नहीं छोड़ा। क्या इन बच्चियों और नवजात के साथ हुई यौन हिंसा के लिए भी उनके कपड़ों, व्यवहार और चाल-चलन को दोषी ठहरायेंगे?

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पूर्व की तुलना में महिलाओं को अब अनेक अधिकार प्राप्त हैं लेकिन इन सबके बावजूद भी उन्हें अपने अस्तित्व और अस्मिता की सुरक्षा का अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है। आए दिन सडको, ट्रेनों, बसों, घरों, खेतों, दफ्तरों में लड़कियां वो सब झेलने को मजबूर होती हैं जो संवैधानिक दृष्टि से भले ही अनैतिक और गैर-कानूनी है लेकिन फिर भी समाज में खुले आम प्रतिदिन होता है मानों उन्हें सामाजिक वैधता प्राप्त हो। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अश्लील फब्तियां, छेड़छाड़, शरीरांगों को गलत तरीके से छूना, दुर्व्यवहार, शारीरिक व मानसिक हिंसा, बलात्कार, अपहरण ऐसे अनेक दुर्व्यवहार लड़कियां प्रतिदिन झेलती हैं। राज्य इन दुर्व्यवहारों के विरुद्ध कानून बना कर या बने हुए कानूनों में संशोधन व परिवर्तन करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड लेते हैं, समितियां गठित कर दी जाती हैं, जाँच बैठा दी जाती है, नतीजों का कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ। मीडिया भी कुछ दिन इन ख़बरों पर अपनी रोटियां सेंकता है फिर उसे कुछ नया मिल जाता है और ऐसी खबरे कहीं दफ़न हो जाती हैं और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा व दुर्व्यवहार का यह खेल बदस्तूर जारी रहता है।

अधिकांश सेमिनारों, कार्यशालाओं और बौद्धिक चर्चाओं में लड़कियों को कुछ इस तरह की सावधानियां रखने की सलाह दी जाती रही है जैसे चाबियों को हथियार समझकर उसका प्रयोग खुद को बचाने के लिए करे, गाड़ी में बैठने से पहले पिछली सीट पर देख लें, मोबाइल फोन में हेल्प लाइन नंबर रखें, रात में बाहर न निकले, सोते समय सभी खिड़कियां बंद कर लें, किसी भी प्रकार का नशा न करें, आप अनजाने लोगों से खाने-पीने की कोई वस्तु न ले, मिर्च स्प्रे साथ रखें। काम से घर जाते समय अपना रास्ता बदलती रहें, अपने कपड़ों पर ध्यान दें, हाईवे के रेस्ट एरिया का इस्तेमाल न करें, अकेले बाहर न जाकर समूह में बाहर जाएं। सवाल यह है कि यह सावधानियां नवजात और किशोरियों को कैसे सिखाएं या फिर इन समस्याओं का हल केवल यही है कि लड़कियों को ही सावधान रहना होगा। क्या वास्तव में इस सब सावधानियों से यौन हिंसा की घटनाएँ रुक जाएँगी।

पंडित जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि किसी भी देश की स्थिति उस देश की महिलाओं की स्थिति को देखकर ज्ञात की जा सकती है। यदि इस तर्क को सही माना जाए तो फिर कैसे हम दावा कर सकते हैं कि हम देश की चौथी सबसे बडी अर्थव्यवस्था हैं। जिस देश की आधी आबादी प्रतिदिन बलात्कार, हिंसा, यौन शोषण, तेजाब हमला, दहेज़ हत्या जैसी घटनाओं का दंश झेलती हो उस देश की स्थिति क्या होगी यह बताने की जरुरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाने या महिला सशक्तीकरण का उद्घोष करने से ही अगर महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाया जा सकता तो अब तक आ चुका होता। एक लेखिका ने लिखा भी है दरअसल सवाल यहाँ महिला सशक्तीकरण का है ही नहीं, उन्हें मजबूत या सशक्त बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे तो पहले से ही मजबूत हैं। जरुरत है दुनिया द्वारा महिलाओं की ताकत को देखने के नजरिए को बदलने की। सच ही तो है अगर पुरुष समाज महिलाओं को देखने का नजरिया बदल ले तो समस्या ही समाप्त हो जाएगी। एक इंसान (पुरुष) को दूसरे इंसान (महिला) के जीवन को निर्धारित करने या निर्देशित करने का अधिकार किसने दिया।

लेखिका ग्लोरिया स्टीनम लिखती हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने शरीर पर अधिकार लोकतंत्र की स्थापना का पहला कदम है और इस आधार पर महिलाएँ विशेष रूप से वे जो नस्ल, जाति या वर्ग के आधार पर अवमूल्यित हैं, अभी भी अंतरंग तानाशाही के अधीन हैं। सवाल यह उठता है कि क्या बलात्कार को सामूहिक आतंकवाद की संज्ञा दी जा सकती है क्योंकि आतंकवाद में भी भय उत्पन्न करके दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और बलात्कार में भी महिला व्यवहार को नियंत्रित करना, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करना, और उन्हें शक्तिहीन साबित करना शामिल होता है। पहले के समय में अधिकांशतः बलात्कार की घटनाओं के लिए अपरिचित/अजनबी जिम्मेदार होता था लेकिन आज तो परिवार का कोई भी सदस्य पति, देवर, पिता, भाई, दादा, नाना, मामा, चाचा और मित्र इन घटनाओं में संलग्न देखा जा सकता है। यह भी एक तथ्य है कि कुछ पूर्वाग्रह बलात्कार की संस्कृति को वैधता प्रदान करते हैं जैसे लड़के तो लड़के ही होते हैं, लड़की का रात को अकेले निकलना, छोटे कपडे पहनना, सबसे हँसकर बात करना, पब में जाकर नशा करना, महिलाओं की न का मतलब हाँ होना इत्यादि। यानी लड़कियों के सोचने, बोलने, पहनने और चलने के तरीको में बलात्कार की संस्कृति अंतर्निहित है।

नारीवादी ऑद्रे लॉर्डे लिखती हैं कि मैं उन महिलाओं के लिए लिखती हूँ जो बोल नहीं पातीं, जिनके पास आवाज़ नहीं है क्योंकि वे बहुत डरी हुई थीं, क्योंकि हमें डर को खुद से ज़्यादा सम्मान देना सिखाया गया है। हमें सिखाया गया है कि चुप्पी हमें बचा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पुरुषों को शिक्षित करें। आज भी महिलाओं से यही अपेक्षा की जाती है कि वे पुरुषों की अज्ञानता की खाई को पाटकर उन्हें हमारे अस्तित्व और हमारी ज़रूरतों के बारे में शिक्षित करें। एक अन्य नारीवादी रूथ बेडर गिन्सबर्ग का मानना है कि औरतों को असली बराबरी तभी मिलेगी जब मर्द उनके साथ अगली पीढ़ी को पालने की ज़िम्मेदारी शेयर करेंगे। एक लैंगिक समानता आधारित समाज वह होगा जहां 'जेंडर' शब्द प्रयुक्त न हो, जहां हर कोई जैसा है वैसा रह सके। इसलिए जरुरत है कि न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाए।

भाषा की राजनीति और राजनीति की भाषा

चिंतन

विवेक रंजन श्रीवास्तव

शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द केवल ध्वनि नहीं रहे, वे मनुष्य की नियति लिखने लगे। सत्ता ने तलवार से पहले शब्दों पर अधिकार करना सीखा, क्योंकि तलवार शरीर को घायल करती है, शब्द चेतना को। इसलिए जहाँ भी राजनीति जन्म लेती है, वहाँ भाषा उसके सबसे विश्वसनीय सेनापति की तरह खड़ी दिखाई देती है। और जहाँ भाषा अपनी सहजता खो देती है, वहाँ समझ लेना चाहिए कि राजनीति ने उसकी उँगली थाम कर उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है।

भाषा किसी वृक्ष की तरह होती है। उसकी जड़ें लोक में होती हैं, तना संस्कृति में और शाखाएँ भविष्य की ओर फैलती हैं। राजनीति उस वृक्ष पर अपने झंडे बाँध देना चाहती है। वह चाहती है कि हर पत्ता उसकी विचारधारा की दिशा में हिले, हर फूल उसकी विजय का रंग धारण करे। किंतु भाषा का स्वभाव हवा जैसा होता है। उसे बाँधा नहीं जा सकता। वह नदी की भांति,अंततः उसी दिशा में बहती है जहाँ मनुष्य की साँस बची रहती है, जहां प्रवाह के लिए वांछित वैचारिक तथा भाषाई विस्तार की लोक व्यवहार की, उपयोगिता और संप्रेषण की संभावना की गहराई होती है।

राजनीति का पहला कौशल शब्दों के अर्थ बदलना है। वह पराजय को रणनीति, समझौते को दूरदर्शिता, विरोध को षड्यंत्र और प्रचार को जनमत कहने से भी नहीं हिचकती है। धीरे-धीरे शब्द अपने पुराने वस्त्र उतार देते हैं और नए अर्थों का परिधान पहन लेते हैं। शब्दकोश मौन रहता है, पर समाज का मानस बदल जाता है। यही राजनीति की सबसे सूक्ष्म विजय होती है। जब भाषा सच नहीं बोलती, बल्कि सच का अभिनय करने लगती है।

चुनाव का मौसम वस्तुतः भाषा का सबसे बड़ा उत्सव नहीं, उसकी सबसे कठिन परीक्षा होता है। भाषा और क्षेत्रीयता की भावनाओं को हथियार बनाना राजनीति जानती है। विपक्ष के प्रति भद्दे शब्द, फूलों की वर्षा की तरह बरसाये जाते हैं। किंतु उनके भीतर जब तक काँटों का अनुशासन छिपा रहता है,वे लोक मर्यादित भाषा में रहे आते हैं। वादे कविता की तरह सुनाई देते हैं, आरोप व्यंग्य की तरह और घोषणाएँ भविष्यवाणी की तरह। जनता हर बार शब्दों की चमक में अपना कल खोजती है, जबकि राजनीति जानती है कि मतदाता की स्मृति क्षणिक होती हैं। इसलिए वह हर चुनाव में नई भाषा गढ़ती है, जैसे गिरगिट कामाफ्लाज कर अवसर के अनुरूप नया रंग धारण करता रहता है।

भाषा की अपनी भी राजनीति है। कोई भाषा राजभवनों तक पहुँच जाती है, कोई लोकगीतों में ही जीवन काट देती है। कोई बोली विद्यालय के द्वार पर ही ठिठक जाती है, तो कोई संसद के गलियारों में अधिकारपूर्वक चलती है। यह केवल व्याकरण का अंतर नहीं, सत्ता के लिए वोटों के वितरण का मानचित्र बनाया जाता है। भाषा का सम्मान दरअसल मनुष्य के सम्मान का दूसरा नाम है। जिस दिन किसी बोली को तुच्छ कहा जाता है, उसी दिन उसके बोलने वाले मनुष्यों की गरिमा भी घायल हो जाती है।

आज यह खेल और भी महीन हो गया है। पहले शब्द भाषणों से निकलते थे, अब वे स्क्रीन से फिसलते हैं। हैशटैग नए नारे हैं, मीम नए व्यंग्य और ट्रोल नई भीड़। सच और झूठ के बीच की दूरी अब शब्दों की नहीं, उनकी गति की हो गई है। जो पहले लोगों के दिलों दिमाग तक पहुँच जाता है, वही अक्सर सत्य मान लिया जाता है। इसलिए राजनीति होड़ करती है। भाषा अब बाज़ार भी है, युद्धभूमि भी और प्रयोगशाला भी, जहाँ हर दिन अर्थों के नए रसायन तैयार किए जा रहे हैं।

फिर भी राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह भाषा का उपयोग तो कर सकती है, स्वामित्व नहीं पा सकती। समय सबसे कठोर संपादक है। वह भाषणों की चकाचौंध से चमकीले वाक्य मिटा देता है और केवल वही शब्द बचाकर रखता है जिनमें मनुष्य की करुणा, न्याय और सत्य की धड़कन होती है। इसी कारण इतिहास में असंख्य नारे धूल हो गए, पर कबीर की उलटबाँसियाँ, तुलसी की चौपाइयाँ, प्रेमचंद की भाषा और दिनकर का ओज आज भी जीवित हैं। साहित्य का शब्द संसार सत्ता के लिए नहीं, समय के लिए रचा जाता है।

वास्तव में भाषा और राजनीति का संबंध दर्पण और चेहरे जैसा है। राजनीति जितनी बार अपना चेहरा बदलती है, भाषा उतनी ही बार नया प्रतिबिंब रचती है। किंतु दर्पण की एक ईमानदारी होती है, वह अंततः चेहरा वैसा ही दिखा देता है जैसा वह है। इसलिए किसी राष्ट्र की असली शक्ति उसकी सेनाओं या संसदों से अधिक , उसकी भाषा की नैतिकता में निहित होती है। जिस दिन शब्द भय से मुक्त होकर सत्य का उच्चारण करने लगते हैं, उसी दिन लोकतंत्र का वास्तविक सूर्योदय होता है। और जिस दिन भाषा केवल सत्ता की प्रतिध्वनि बनकर रह जाती है, उसी दिन सभ्यता का सांध्यकाल आरंभ हो जाता है। इसलिए साहित्यकार की समाज के प्रति जवाबदारी बहुत ज्यादा होती है।भाषा को राजनीति के गंदे खेल से बचाना केवल व्याकरण को बचाना नहीं, मनुष्य की स्वतंत्र आत्मा को बचाना है।

नशे से दूरी है जरूरी: मानसिक स्वास्थ्य का भी अभियान

मुद्दा

डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी

वरिष्ठ मनोचिकित्सक, भोपाल

'नशे से दूरी है ज़रूरी' केवल एक सरकारी नारा नहीं, बल्कि समाज के मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक स्वास्थ्य की रक्षा का संदेश है। मध्यप्रदेश पुलिस का यह अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नशा केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का विषय भी है। अधिकांश लोग मानते हैं कि नशा केवल इच्छाशक्ति की कमजोरी है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। शराब, गांजा, अफीम, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स और अन्य मादक पदार्थ मस्तिष्क के उन हिस्सों को प्रभावित करते हैं जो आनंद, निर्णय क्षमता, आत्म-नियंत्रण और प्रेरणा को नियंत्रित करते हैं। समय के साथ व्यक्ति का मस्तिष्क इन पदार्थों पर निर्भर होने लगता है और फिर नशा उसकी पसंद नहीं, बल्कि मजबूरी बन जाता है। मनोचिकित्सकीय दृष्टि से देखा जाए तो अनेक लोग तनाव, अवसाद, चिंता, अकेलेपन, असफलता, पारिवारिक संघर्ष या साथियों के दबाव से बचने के लिए नशे की शुरुआत करते हैं। यह शुरुआत अक्सर 'सिर्फ एक बार' से होती है, लेकिन धीरे-धीरे यही आदत लत में बदल सकती है। इसलिए नशे की रोकथाम केवल पदार्थों की उपलब्धता कम करने से नहीं होगी, बल्कि उन मानसिक और सामाजिक कारणों को भी समझना होगा जो लोगों को नशे की ओर धकेलते हैं।

नशे का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। इसका असर परिवार, बच्चों, सड़क सुरक्षा, घरेलू हिंसा, अपराध, कार्यक्षमता और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। अनेक सड़क दुर्घटनाओं, हिंसक घटनाओं, आत्महत्या के प्रयासों और पारिवारिक टूटन में नशा एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता होता है।

इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब समाज नशे से जूझ रहे व्यक्ति को केवल अपराधी या चरित्रहीन मानने के बजाय उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्ति के रूप में भी देखना सीखे। इसका अर्थ अपराध को नज़रअंदाज़ करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि नशे की समस्या का प्रभावी समाधान कानून और उपचार–दोनों के संतुलित प्रयासों से ही संभव है।

माता-पिता, शिक्षक और समाज की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों के साथ खुला संवाद, भावनात्मक सहयोग, सकारात्मक वातावरण और वैज्ञानिक जानकारी उन्हें नशे से दूर रखने के सबसे प्रभावी उपाय हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य तथा नशामुक्ति पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति नशे की समस्या से जूझ रहा है, तो उसे शर्म या भय के कारण उपचार से दूर नहीं रहना चाहिए। आज दवाओं, मनोचिकित्सकीय परामर्श, मनोचिकित्सा और पुनर्वास की प्रभावी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। समय पर उपचार मिलने से अधिकांश लोग स्वस्थ और सामान्य जीवन में वापस लौट सकते हैं।

अंततः 'नशे से दूरी है ज़रूरी' केवल मध्यप्रदेश पुलिस का अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार, विद्यालय, चिकित्सक और नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। जब कानून, समाज और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ मिलकर कार्य करेंगी, तभी नशामुक्त, सुरक्षित और स्वस्थ समाज का लक्ष्य वास्तव में प्राप्त किया जा सकेगा।

संपूर्ण क्रिकेटर गैरी सोबर्स का अवसान

सोबर्स केवल आँकड़ों का दूसरा नाम नहीं थे; वे उस दुर्लभ क्रिकेटीय कल्पना के साकार रूप थे जिसमें एक अकेला खिलाड़ी मैच का पूरा स्वरूप बदल सकता है। बाएँ हाथ के बल्लेबाज़ के रूप में वे दुनिया के सबसे तेज़ गेंदबाज़ों के सामने भी सहजता और आक्रामकता का अद्भुत संतुलन बनाए रखते थे। वही खिलाड़ी नई गेंद से तेज़-मध्यम गेंदबाज़ी कर सकता था, ज़रूरत पड़ने पर बाएँ हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन भी डाल सकता था और चाइनामैन भी। स्लिप में खड़े हों तो कैच ऐसे पकड़ते मानो गेंद पहले से उनकी हथेलियों का रास्ता जानती हो।

स्मृति शेष

आदित्य दुबे

लेखक वेबसाइट ई अंतर्भव के प्रबंध संचालक हैं।

भारत में क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर की चर्चा हो तो अधिकांश लोगों की पहली पसंद कपिल देव होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में यही प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर जैक्स कैलिस होगा। इंग्लैंड की कई पीढ़ियाँ आज भी इयान बॉथम को सर्वोच्च मानती हैं। न्यूज़ीलैंड में रिचर्ड हैडली, पाकिस्तान में इमरान खान और बांग्लादेश में शाकिब अल हसन के पक्ष में भी गहरी भावनाएँ हैं। हर देश को अपने महानायक पर गर्व करने का अधिकार है।

लेकिन जब चर्चा राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर क्रिकेट के पूरे इतिहास की होने लगे, तब एक नाम लगभग निर्विवाद रूप से सामने आता है–सर गारफील्ड 'गैरी' सोबर्स। उनके निधन के साथ केवल वेस्ट इंडीज़ ने अपना महानायक ही नहीं खोया है, बल्कि क्रिकेट ने वह कसौटी खो दी, जिस पर पिछले छह दशकों से हर महान ऑलराउंडर को परखा जाता रहा। 89 वर्ष की आयु में उनका जाना केवल एक खिलाड़ी का निधन नहीं, बल्कि क्रिकेट के एक ऐसे युग का अवसान है जिसकी प्रतिध्वनि आने वाली पीढ़ियाँ भी सुनती रहेंगी।

सोबर्स केवल आँकड़ों का दूसरा नाम नहीं थे; वे उस दुर्लभ क्रिकेटीय कल्पना के साकार रूप थे जिसमें एक अकेला खिलाड़ी मैच का पूरा स्वरूप बदल सकता है। बाएँ हाथ के बल्लेबाज़ के रूप में वे दुनिया के सबसे तेज़ गेंदबाज़ों के सामने भी सहजता और आक्रामकता का अद्भुत संतुलन बनाए रखते थे। वही खिलाड़ी नई गेंद से तेज़-मध्यम गेंदबाज़ी कर सकता था, ज़रूरत पड़ने पर बाएँ हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन भी डाल सकता था और चाइनामैन भी। स्लिप में खड़े हों तो कैच ऐसे पकड़ते मानो गेंद पहले से उनकी हथेलियों का रास्ता जानती हो।

आज क्रिकेट में 'थ्री-डायमेंशनल प्लेयर'की चर्चा होती है, लेकिन सोबर्स उस परिभाषा से भी आगे थे। वे केवल बहुआयामी नहीं, बल्कि लगभग असीम संभावनाओं वाले क्रिकेटर थे। उन्हें किसी एक भूमिका, किसी एक शैली या किसी एक विशेषता में बाँधना संभव ही नहीं था।

यही कारण है कि कपिल देव, जैक्स कैलिस, इयान बॉथम, इमरान खान या बेन स्टोक्स जैसे महान खिलाड़ियों की चर्चा अंततः सोबर्स की कसौटी तक पहुँच जाती है। कपिल ने भारत को पहला विश्व कप दिलाया। कैलिस ने अद्भुत निरंतरता का मानक स्थापित किया। बॉथम ने एशेज़ की सबसे यादगार कहानियाँ लिखीं। इमरान खान ने नेतृत्व, व्यक्तित्व और प्रदर्शन–तीनों से इतिहास रचा। इन सबकी उपलब्धियाँ अपने-अपने संदर्भ में असाधारण हैं, लेकिन सोबर्स का व्यक्तित्व इन सभी गुणों का संगम था। वे विश्वस्तरीय बल्लेबाज़ थे, प्रभावशाली गेंदबाज़ थे और असाधारण क्षेत्ररक्षक भी। इसलिए क्रिकेट इतिहास ने उन्हें केवल महान ऑलराउंडर नहीं, बल्कि 'सबसे संपूर्ण क्रिकेटर' का दर्जा दिया।

उनका 365* का विश्व रिकॉर्ड, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्कों का ऐतिहासिक कारनामा और लगभग दो दशकों तक वेस्ट इंडीज़ के लिए निभाई गई उनकी केंद्रीय भूमिका आज भी किंवदंती का हिस्सा हैं। लेकिन उनकी महानता इन उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी।

सोबर्स का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने क्रिकेट की संभावनाओं का दायरा बढ़ाया। उन्होंने सिद्ध किया कि किसी खिलाड़ी को किसी एक साँचे में सीमित नहीं किया जा सकता। वे परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेते थे और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। आज, जब क्रिकेट विशेषज्ञता का खेल बन चुका है–जहाँ बल्लेबाज़, गेंदबाज़ और फिनिशर अलग-अलग भूमिकाओं में बाँटे जाते हैं–सोबर्स की विरासत और भी विराट दिखाई देती है। वे उस दौर में भी आधुनिक थे, जब आधुनिक क्रिकेट की अवधारणा अभी जन्म ही ले रही थी।

वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के स्वर्णिम युग की बुनियाद भी काफी हद तक सोबर्स की पीढ़ी ने ही रखी। बाद में क्लाइव लॉयड और विवियन रिचर्ड्स की टीमों ने विश्व क्रिकेट पर जो दबदबा कायम किया, उसकी नींव पहले ही तैयार हो चुकी थी। कैरेबियाई क्रिकेट को आत्मविश्वास, सम्मान और वैश्विक पहचान दिलाने में सोबर्स का योगदान किसी विश्व कप विजय से कम नहीं आँका जा सकता। वे केवल महान खिलाड़ी नहीं थे; वे उस सांस्कृतिक आत्मविश्वास के प्रतीक थे जिसने छोटे-छोटे कैरेबियाई द्वीपों को क्रिकेट की महाशक्ति बना दिया।

आज सोशल मीडिया के दौर में महानता की बहसें अक्सर आँकड़ों तक सिमट जाती हैं। बल्लेबाज़ी औसत, स्ट्राइक रेट, विकेट, कैच और रिकॉर्ड–सब कुछ तुलना का आधार बन जाता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी आँकड़ों से कहीं बड़े होते हैं। सोबर्स उन्हीं विरले खिलाड़ियों में थे। जिन्होंने उन्हें खेलते देखा, उनका कहना था कि उन्हें समझने के लिए स्कोरकार्ड पर्याप्त नहीं; आँखों की गवाही चाहिए। वे क्रिकेट केवल खेलते नहीं थे, उसे कला में रूपांतरित कर देते थे।

यही कारण है कि उनके समकालीनों से लेकर आधुनिक युग के दिग्गजों तक, लगभग सभी ने उन्हें क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर माना। उनके निधन पर दुनिया भर के क्रिकेट बोर्डों, पूर्व खिलाड़ियों और प्रशंसकों द्वारा व्यक्त शोक इस सार्वभौमिक सम्मान का प्रमाण है। सर गैरी सोबर्स के जाने से क्रिकेट अनाथ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी विरासत अमर रहेगी। लेकिन यह खेल निस्संदेह थोड़ा अकेला हो गया है।

आने वाले वर्षों में नए ऑलराउंडर उभरेंगे, नए रिकॉर्ड बनेंगे और नई पीढ़ियाँ अपने-अपने नायकों को चुनेंगी। भारत फिर कपिल देव को याद करेगा, दक्षिण अफ्रीका कैलिस को और इंग्लैंड बॉथम को। यह स्वाभाविक भी है। किंतु जब प्रश्न यह होगा कि क्रिकेट ने अब तक का सबसे संपूर्ण खिलाड़ी किसे देखा, तो इतिहास शायद फिर उसी नाम पर ठहर जाएगा–सर गैरी सोबर्स।

कुछ महान खिलाड़ी अपने देश के होते हैं, कुछ अपने युग के। लेकिन कुछ विरले ऐसे होते हैं जो पूरे खेल की साझा धरोहर बन जाते हैं। सर गैरी सोबर्स उसी विरल परंपरा के सबसे उज्ज्वल प्रतीकों में थे।

क्रिकेट का वह ऋषि अब मैदान पर नहीं उतरेगा, लेकिन जब भी कोई युवा खिलाड़ी बल्ले, गेंद और क्षेत्ररक्षण–तीनों में उत्कृष्ट बनने का सपना देखेगा, वह अनजाने ही सोबर्स की विरासत का अनुसरण कर रहा होगा। किसी खिलाड़ी की अमरता शायद इससे बड़ी नहीं हो सकती।

सरोकार

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक संभकार हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी पेंशनरों को सौगात

आखिरकार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 25 साल से चली आ रही पेंशनरों की मांग को मान लिया और उन्होंने पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में वृद्धि के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य से सहमति लेने की प्रचलित परंपरा को खत्म कर दिया। अब मध्यप्रदेश के और छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को राज्य शासन द्वारा बढ़ाई गई महंगाई राहत तुरंत मिल सकेगी। इस निर्णय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की भी अहम भूमिका है।

मध्यप्रदेश के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनीष रस्तोगी और छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव द्वारा संयुक्त रूप से जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को देय महंगाई राहत में वृद्धि के संबंध में वर्तमान में प्रचलित पारस्परिक सहमति की प्रक्रिया है। उक्त प्रक्रिया पर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्विचार किया गया तथा प्रशासनिक सुगमता एवं पेंशनरों के हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए हैं-

(क) महंगाई राहत घोषित करने हेतु दूसरे राज्य की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। (ख) पेशनरों को देय पेंशन राहत में वृद्धि हेतु विधायी संशोधन के स्थान पर दोनों राज्यों द्वारा सीधे कार्यकारी आदेश जारी करेंगे। (ग) राज्यों के आदेश से वृद्धि के फलस्वरूप पड़ने वाले वित्तीय भार के संबंध में मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ शासन को सूचना हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा। (घ) कोई भी राज्य केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मंहगाई राहत की दरों से अणिक दर घोषित नहीं करेगा। उक्त आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील रहेगा। मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा उक्त आदेश 17 जुलाई 2026 को जारी किया गया। इस आदेश के दूरगामी परिणाम होंगे। पहले दोनों राज्य सरकार जब भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगााई भत्ता घोषित करती थी तो आदेश के दिनांक से कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का लाभ मिल जाया करता था। किन्तु पेंशनरों की महंगाई राहत की दरों में वृद्धि के लिए मध्यप्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगती थी। इसमें कई महीनों का समय लग जाता था। और जब भी छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति प्राप्त होती थी, उस दिनांक से मध्यप्रदेश सरकार मंहगाई राहत का आदेश जारी करती थी। इसमें होता यह था कि जब भी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता था तो उसके कई महीनों बाद पेशनरों को महंगाई राहत मिल पाती थी। इससे पेंशनरों का काफी आर्थिक नुकसान होता था। यह नाइंसाफी पिछले कई सालों से चल रही थी।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य सरकारों ने मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को समाप्त या विलोपित नहीं किया है। कोई भी राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम को समाप्त या विलोपित नहीं कर सकती। यह अधिकारकेन्द्र सरकार को ही है। इसलिए दोनों राज्य सरकारों ने बीच का रास्ता निकाला और उक्त आदेश के (ख) के द्वारा पेंशनरों को देय महंगाई राहत में वृद्धि हेतु विधायी संशोधन के स्थान पर दोनों राज्यों द्वारा सीधे कार्यकारी आदेश जारी किए गए।

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों की सदाशयता से दोनों राज्यों के लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है। इससे पेंशनरों की और पेंशनर संगठनों की 25 साल से चली आ रही मांग को दोनों राज्य सरकारों ने मानकर पेंशनरों को महंगाई राहत देने का आखिरकार रास्ता निकाल ही लिया। यदि दोनों राज्य सरकारें पेंशनरों के हित में मध्यप्रदेश पुनर्गठन 2000 की धारा 49 (6) को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजती तो इसमें कितना समय लगता? इसकी कोई ग्यारंटी नहीं थी। इसलिए बहुत सोच समझकर दोनों राज्य सरकारों ने बीच का रास्ता निकालकर पेंशनरों के लिए सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए दोनों राज्य सरकारों और मुख्यमंत्रियों को साधुवाद!

सिद्ध महराज के पास गौशाला की भूमि अतिक्रमणमुक्त कराने को लेकर एसडीएम डॉ. बबीता राठौर से मुलाकात की

सोहागपुर। सोहागपुर ही नहीं क्षेत्र के विख्यात सिद्ध महाराज के समीप सिटीया गोहना गौशाला की लगभग 16 एकड़ शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण एवं मजार निर्माण के संबंध में सकल हिंदू समाज एवं नागरिक संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अनुविभागीय अधिकारी डॉ. बबीता राठौर से मुलाकात की इस प्रतिनिधिमंडल में समाजसेवी कृष्णा पालीवाल, पत्रकार संघ अध्यक्ष पवनसिंह चौहान, पत्रकार अमित बिल्लौरे, वकील शिवकुमार पटेल, समाजसेवी विशाल गोलानी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रीतेन्द्र सिंह राजपूत, पूर्व जिला बजरंग दल रूपेश रघुवंशी, पूर्व बजरंग दल जिला

सुरक्षा संयोजक आशीष पुरोहित आदि शामिल थे।प्रतिनिधिमंडल ने अनुविभागीय अधिकारी डॉ. बबीता राठौर से आग्रह किया कि क्षेत्र के प्रसिद्ध सिद्ध महराज के समीप गौशाला की करीबन 16 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया गया। इस अतिक्रमण की संपूर्ण शासकीय भूमि का राजस्व अभिलेखों के अनुसार सीमांकन कराया जाए। सीमांकन के उपरांत यदि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत हटाकर पूरी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शासकीय भूमि का संरक्षण तथा उसका वैधानिक उपयोग सुनिश्चित किया जाना जनहित एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण विषय है। प्रतिनिधि मंडल के प्रतिनिधि एवं वकील शिवकुमार पटेल ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि गौ शाला की संपूर्ण 16 एकड़ भूमि का राजस्व अभिलेखों के आधार पर परीक्षण एवं सीमांकन कराया जाएगा।

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान का पुतला दहन, सांसद दर्शनसिंह आदि के विरुद्ध नारेबाजी

सोहागपुर। किसान कांग्रेस का शत-प्रतिशत मूंग खरीदी को लेकर 'गांव-गांव पुतला दहन' आंदोलन जारी है। इसी तारतम्य में आज सोहागपुर के मुख्य बाजार नर्मदापुरम पिपरिया राज्य मार्ग 22 पर शत-प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसान कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान कांग्रेस के तत्वावधान में हो रहे इस आन्दोलन को सभी कांग्रेस जनों ने एकत्रित होकर किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले का दहन किया गया। पुतला दहन के अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते करते यकायक क्षेत्रीय सांसद दर्शनसिंह के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। इसी बीच पुतला दहन के समय पुलिसकर्मियों ने पुतले पर पानी डालने एवं पुतला छीनने की कोशिश असफल कोशिश की गई। किसान कांग्रेस के तत्वावधान में चलाए जा रहे निरंतर 'गांव-गांव पुतला दहन कार्यक्रम' के तहत क्षेत्र के किसान अपनी मांगों शत-प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग को लेकर पूरी तरह अडिग नजर आ रहे हैं। उक्त आन्दोलन प्रदर्शन वरिष्ठ किसान नेता पुष्पराजसिंह पटेल एवं जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष बाबू चौधरी के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित किए जा रहे हैं । पुतला दहन के अवसर पर संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की वर्तमान नीतियां किसान विरोधी हैं।यह सरकार किसानों के हितों की निरंतर अनदेखी कर रही है। मूंग की शत-प्रतिशत मूंग न खरीदे जाने से क्षेत्र का अन्नदाता आर्थिक संकट से जूझ रहा है। नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार किसानों की शत-प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग को स्वीकार नहीं करती तब तक चरणबद्ध आंदोलन तथा गांव-गांव में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान आदि के पुतला दहन का सिलसिला जारी रहेगा।

भोपाल की कंपनी को मिला बैतूल -इटारसी के बीच फोरलेन निर्माण का ठेका

● 700 करोड़ में बनेगी 21 किमी फोरलेन सड़क, आवागमन होगा सुगम

बैतूल। बैतूल-इटारसी फोरलेन के बीच बचे 21 किमी सडक़ निर्माण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। सिर्फ हाईकोर्ट से स्टे हटाने की देरी है। जैसे ही स्टे हटेगा, सडक़ निर्माण का काम शुरू कर दिया जायेगा। फिलहाल सडक़ निर्माण को लेकर टैंडर भी हो चुके है। एनएचएआई द्वारा भोपाल की एक कंपनी को टेंडर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 21 किमी सडक़ निर्माण के इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 700 करोड़ रूपये खर्च होगे। इधर टैंडर प्रक्रिया के बाद कंपनी द्वारा प्लांट लगाने के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। वन क्षेत्र में आने वाले इस क्षेत्र में वन्य जीवों की आवाजाही के लिए जगह-जगह अंडरपास और ओवरपास बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद लगभग दो से ढाई साल की अवधि में उक्त प्रोजेक्ट पूर्ण किया जाएगा। बरेठा सहित धार और केसला वन क्षेत्र में फोरलेन सडक़ निर्माण होने से भोपाल तक का सफर आसान हो जाएगा। बता दे कि बैतूल जिले के बरेठा सहित नर्मदापुरम के धार और केसला में आने वाली इस सडक़ के निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक लगी थी। जिसके कारण यह सडक़ नहीं बन पाई और इटारासी-बैतूल के माध्यम लगभग 21 किलोमीटर का भाग शेष रह गया था। लेकिन फोरलेन बनाने के लिए एनएचएआई ने हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप प्लान बना लिया है और वाइल्ड लाइफ बोर्ड एवं केंद्र सरकार से सभी जरुरी अनुमतियां भी प्राप्त कर ली है। अब हाईकोर्ट का स्टे औपचारिक रूप से हटते ही यहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

आसानी हो जायेगा नागपुर-भोपाल का सफर- नागपुर-भोपाल जैसी दो बड़े महानगरों को जोडऩे वाले नेशनल हाइवे पर अब तक अवरोध बैतूल जिले में स्थित बरेठा घाट बचा है। भोपाल और नागपुर के बीच आवागमन को सुगम और तेज करने के लिए वैसे तो कई साल पहले बैतूल से नागपुर और बैतूल से भोपाल के लिए फोरलेन

नेशनल हाईवे को एक साथ मंजूरी मिली थी। इसमें से बैतूल से नागपुर तक 173.3 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे (एनएच-47) बहुत पहले बन कर तैयार हो चुका। इसके विपरीत बैतूल से इटारसी के बीच 21 किमी के क्षेत्र में सडक निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट की रोक थी। नागपुर (महाराष्ट्र) के एक एनजीओ ने टाइगर कॉरिडोर और बाघ मूवमेंट होने के कारण इस 21 किमी निर्माण कार्य नहीं किए जाने पर स्टे लेकर रखा है। हालांकि यह स्टे अभी हटा नहीं है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सूत्रों के अनुसार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के स्टे के बाद जिन आवश्यक अनुमतियों की जरूरत थी, उनमें वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी स्वीकृतियों सहित अन्य केंद्रीय मंजूरियां अब प्राप्त हो चुकी हैं।

अंडरपास और ओवरपास भी बनेंगे- सडक़ निर्माण के दौरान चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का स्थायी समाधान किया जाएगा। इसके लिए विशेष रेक्टिफिकेशन प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत माइनर ब्रिज बनाए जाएंगे। साथ ही बॉक्स कलवर्ट पर कार्य किया जाएगा, जिसमें चौडीकरण और आवश्यक सुधार शामिल है। ट्रैफिक की निर्बाध और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे अंडरब्रिज, रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण भी होगा। इससे सडक की क्षमता बढ़ेगी और ट्रैफिक बिना रुकावट के चलते रहेगा। इस प्रोजेक्ट को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, ताकि आने वाले वर्षों में भी यह मार्ग सुरक्षित, सुगम और भरोसेमंद बना रहे। वर्तमान में मौजूद टू लेन सडक को फोरलेन में विकसित किया जाएगा, जिसमें सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी और बढ़ते ट्रैफिक के दबाव से राहत मिलेगी। रोजाना लगने वाले लंबे ट्रॉफिक जाम की समस्या कम होगी।

हाईकोर्ट में दायर पीआईएल के बाद से रूका है काम -इटारासी-बैतूल के माध्यम बरेठा घाट का लगभग 21 किलोमीटर का भाग शेष रह गया था। इसमें केसला रेज, भौरा रेंज तथा बरेठा घाट के तीन खंड (कुल 20.91 किमी) सम्मिलित है। ये सभी खंड वन्यजीव, विशेषकर टाइगर मुवमेंट कॉरिडोर के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। इसी के चलते इन खंडों में निर्माण कार्य को 1 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्टे आदेश के पश्चात सथगित कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न वैधानिक एवं पर्यावरणीय विशेष रूप से वन्यजीव संबंधों मंजूरियों की आवश्यकता थी। हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए एनएचएआई ने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरुप पूरी कर ली है। प्रोजेक्ट के लिए वाइल्ड लाइफ बोर्ड एवं केन्द्र सरकार से सभी आवश्यक मंजूरिया प्राप्त हो चुकी है। अब अब उच्च न्यायालय द्वारा स्टे के औरचारिक रूप से हटने के संबंध में आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। जैसे ही न्यायालय से इसे संबंध में निर्देश प्राप्त होंगे, एनएचएआई द्वारा शेष बचे सेक्शन में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

दो से ढाई साल में होगा निर्माण पूर्ण- फोरलेन निर्माण कार्य शुरू होने के बाद लगभग 2 से ढाई साल में सडक़ निर्माण पूर्ण किया जाएगा। एनएचएआई सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद अगले कुछ समय में सडक़ निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बरेठा घाट में लगभग 7 किमी सडक़ बनने के साथ ही धार और केसला के वन क्षेत्रों को मिलाकर कुल 21 किलोमीटर सडक़ निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि टेंडर लेने वाली कंपनी द्वारा तीनों स्थानों पर कैंप बनाने जगह देखी जा रही है। तीनों स्थान पर सडक़ निर्माण होने के बाद बैतूल से भोपाल तक फोरलेन पूर्ण हो जाएगा और राजधानी का सफर आसान हो जाएगा। अभी हालात यह है कि बरेठा घाट में सबसे ज्यादा जाम की स्थिति निर्मित होती है। इस घाट सेक्सन को सडक सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील माना जाता है।

युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है, भारत के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाएं : विधायक विजयपालसिंह

सोहागपुर। युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उक्त उद्गार कार्यक्रम मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने भारतीय जनता पार्टी मंडल सोहागपुर के तत्वावधान में सोहागपुर विधायक कार्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम एवं नव मतदाता संवाद के

अवसर पर कहें। इस अवसर नगर परिषद अध्यक्ष लता यशवंत पटेल, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सुरेश पटेल, वरिष्ठ वकील जेपी माहेश्वरी,संतोष तिवारी, अंजनी पटेल मुख्य रूप से उपस्थित थे । क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने आगे कहा कि भाजपा केवल सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति नहीं करती है । बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के संकल्प के साथ कार्य करती है। जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। आपने अपने उद्बोधन में बड़े ही मार्के की बात कही कि यदि कोई उन पर भ्रष्टाचार का एक भी प्रमाण सिद्ध कर दे ।तो वे उसी दिन सार्वजनिक जीवन छोड़ देंगे। आपने अपने विस्तृत सारगर्भित उद्बोधन में आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोहागपुर को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की सौगात मिल चुकी है तथा आने वाले समय में मुहासा औद्योगिक क्षेत्र में लगभग एक लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आपने युवाओं से उद्योग लगाने का आह्वान किया । ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़े। आपने अंत में नव मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए मतदान करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर की वक्ताओं ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकसित भारत के संकल्प, युवाओं के भविष्य, रोजगार, शिक्षा, उद्यमिता और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर सारगर्भित विस्तृत संवाद किया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्वनी सरोज, जिला भाजयुमो अभिनव पालीवाल, पार्षद रविशंकर उइके, पार्षद गौरव पालीवाल, पार्षद आशीष विश्वकर्मा, भाजपा नेता केशव जाजू शोभापुर सहित कई भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे कार्यक्रम का संचालन अनिल गैरिया ने किया। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले से 260 श्रद्धालु हरिद्वार-ऋषिकेश रवाना

बैतूल। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत बैतूल जिले के लगभग 260 श्रद्धालुओं को रविवार को हरिद्वार-ऋषिकेश की चार दिवसीय तीर्थ यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारा रवाना किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बुजुर्ग यात्रियों का पुष्पहार पहनाकर आत्मीय स्वागत किया, उनका आशीर्वाद लिया तथा हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, अपर कलेक्टर वंदना जाट, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंदिरा महतो सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बुजुर्गों के सम्मान और उनकी आस्था को समर्पित एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि जीवनभर परिवार और समाज की सेवा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने का अवसर देना सरकार की संवेदनशील सोच का परिचायक है। उन्होंने यात्रियों से यात्रा के दौरान आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने, देश की सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने तथा प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी यात्रियों के सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यह हरिद्वार-ऋषिकेश यात्रा 19 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। यात्रा के लिए बैतूल जिले से कुल 260 यात्रियों का चयन किया गया है।

धार में 1.90 करोड़ खर्च कर लगाए गए पौधे सूखे

मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत काटे गए थे हजारों पेड़, भरपाई के लिए किया गया था प्लांटेशन

धार (नप्र)। धार जिले के सरदारपुर वन परिक्षेत्र की कौद बीट के ग्राम शेरगढ़ में मेट्रो रेल परियोजना के तहत काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए किया गया वृक्षारोपण सवालों के घेरे में है।

वन विभाग ने करीब तीन महीने पहले 30.178 हेक्टेयर क्षेत्र में 30,178 पौधे लगाए थे, लेकिन अब इनमें से हजारों पौधे सूख चुके हैं। कई जगह पौधों का नामोनिशान तक नहीं है। जहां पौधे लगाए गए थे, वहां अब सिर्फ सूखे डंठल दिखाई दे रहे हैं। इस वृक्षारोपण पर करीब 1 करोड़ 91 लाख 77 हजार रुपए खर्च किए गए थे। इसका उद्देश्य मेट्रो रेल परियोजना में कटे पेड़ों की भरपाई करना और क्षेत्र में हरियाली बढ़ाना था। लेकिन मौजूदा स्थिति योजना की सफलता पर सवाल खड़े कर रही है।

कई जगह सिर्फ सूखे डंठल बचे- मौके पर बड़ी संख्या में पौधे सूखे मिले। कई स्थानों पर पौधों का अस्तित्व तक नहीं दिख रहा है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि पौधारोपण के बाद उनकी देखभाल और निगरानी कितनी गंभीरता से की गई।

सिर्फ पौधे लगाना काफी नहीं

विशेषज्ञों के अनुसार, वृक्षारोपण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होता। उनकी नियमित सिंचाई, सुरक्षा और देखभाल भी उतनी ही जरूरी होती है। यदि पौधारोपण के बाद रखरखाव नहीं किया जाए, तो करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। शेरगढ़ का यह मामला भी इसी ओर इशारा करता है।

सरकारी खर्च और निगरानी पर सवाल

सरकार हर साल पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाती है। ऐसे में यदि कटे पेड़ों की भरपाई के लिए लगाए गए हजारों पौधे शुरुआती तीन महीनों में ही सूख जाएं, तो योजनाओं की निगरानी और जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। वृक्षारोपण अभियान की सफलता केवल पौधे लगाने से नहीं, बल्कि उनके जीवित रहने से तय होती है। यदि शुरुआती महीनों में ही बड़ी संख्या में पौधे नष्ट हो जाएं, तो करोड़ों रुपए खर्च करने का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

बैंक राष्ट्रीयकरण की 57वीं वर्षगांठ पर एआईबीओसी मप्र इकाई का 'हरित संकल्प'

100 से अधिक पौधों का रोपण, विभिन्न बैंकों के सैकड़ों अधिकारियों ने एकजुट होकर दिया पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश

भोपाल। बैंक राष्ट्रीयकरण की 57वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC), मध्यप्रदेश इकाई द्वारा जम्बूरी मैदान, BHEL, भोपाल में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैंकिंग इतिहास के इस महत्वपूर्ण अवसर को सामाजिक सरोकार और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए 100 से अधिक पौधों का रोपण किया गया तथा उनके संरक्षण एवं संवर्धन का सामूहिक संकल्प लिया गया।

कार्यक्रम की विशेषता रही कि AIBOC के विभिन्न घटक संगठनों से जुड़े भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहित विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के सैकड़ों अधिकारी साथी एक मंच पर एकजुट हुए। बैंकिंग बिरादरी की इस व्यापक सहभागिता ने संगठनात्मक एकता, सामाजिक प्रतिबद्धता और पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश दिया। AIBOC के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, 'बैंक राष्ट्रीयकरण केवल बैंकों के स्वामित्व में परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारतीय बैंकिंग को जनोन्मुखी बनाने वाली ऐतिहासिक सामाजिक-आर्थिक पहल थी। इसने किसान, श्रमिक, छोटे उद्यमी और समाज के वंचित वर्गों तक संस्थागत बैंकिंग की पहुँच का विस्तार किया। आज उसी जनकल्याण की भावना को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना इस ऐतिहासिक अवसर की सार्थक अभिव्यक्ति है।'

AIBOC मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुबिन सिन्हा ने कहा, 'राष्ट्र निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी रही है। आज विभिन्न बैंकों के सैकड़ों अधिकारियों का पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट होना दर्शाता है कि बैंक अधिकारी अपने व्यावसायिक दायित्वों के साथ समाज और आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी पूरी प्रतिबद्धता से निभा रहे हैं।'

AIBOC मध्यप्रदेश इकाई के सचिव दिनेश झा ने कहा, 'हमारा उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षित एवं विकसित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित विरासत तैयार करना है। आज लगाया गया प्रत्येक पौधा स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है।'

इस वृहद पौधारोपण अभियान को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी स्वरूप देने में पर्यावरण हितैषी एवं SBI ऑक्सीजन बैंक के संस्थापक डॉ. पंकज भारती का विशेष सहयोग रहा। उनकी देखरेख एवं मार्गदर्शन में पौधों के चयन, व्यवस्थित रोपण तथा उनके भावी संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अभियान को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके निरंतर प्रयासों एवं अनुभव ने इस अभियान को विशेष सार्थकता प्रदान की।

कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अम्बरीष नंदा, पंजाब नेशनल बैंक के जनरल सेक्रेटरी निर्भय सिंह, यूनियन बैंक ऑफिसर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी दीपक नायर, यूको बैंक के पदाधिकारी सुमित मिश्रा, इंडियन बैंक के प्रशांत रघुवंशी, जयंत सेन, कपिला मेघानी, अमित प्रजापति एवं अभिमन्यु राय, AIBOC मीडिया प्रभारी अरविंद पंडियार तथा केनरा बैंक के मनीष चतुर्वेदी सहित विभिन्न घटक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता की।

संक्षिप्त समाचार

मानोरा मेले में परिवहन विभाग की सघन जांच

8 वाहनों पर चालानी कार्रवाई

विदिशा,(निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशों के पालन में जिला परिवहन विभाग द्वारा मानोरा मेले में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानोरा रोड पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन अधिकारी श्री गिरिजेश वर्मा ने किया। जांच अभियान के दौरान मानोरा मेले की ओर जा रहे यात्री वाहनों एवं अन्य वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान परिवहन नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित 8 वाहन पाए गए, जिनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 76,700 रुपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। जिला परिवहन अधिकारी श्री गिरिजेश वर्मा ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं की अधिक आवाजाही को देखते हुए यात्री वाहनों की विशेष रूप से जांच की जा रही है। वाहन चालकों को निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाने, सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने, फिटनेस एवं परमिट नियमों का पालन करने तथा सुरक्षित एवं सावधानीपूर्वक वाहन संचालन के निर्देश दिए गए।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर शिविर लगाकर किया गया 724 बच्चों का टीकाकरण

सीहोर ,(निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिलेभर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं एवं अनेक स्थानों पर प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत शिविर लगाकर टीकाकरण के साथ ही बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। इसी क्रम में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के तहत जिले में 17 जुलाई को आयोजित शिविरों में शून्य से एक वर्ष की आयु के 497 बच्चों तथा एक वर्ष से अधिक आयु के 227 बच्चों का टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही 108 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषि दीदियों को दिया गया प्रशिक्षण

सीहोर ,(निप्र)। एसआरएलएम एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा स्थानीय बीजों के संरक्षण, उनकी देखरेख तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीहोर में कृषि दीदियों का एक दिवसीय सामर्थ्य निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान स्थानीय बीजों के संरक्षण, बीज बैंक की अवधारणा, बीज उपचार, प्राकृतिक खेती की तकनीकों तथा गांव स्तर पर किसानों के बीच इन नवाचारों के प्रसार पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि दीदियों को स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक खेती के प्रभावी संवाहक के रूप में सशक्त बनाना था, ताकि वे किसानों को स्थानीय बीजों के संरक्षण, जैविक उपायों एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक कर सकें।

अवैध शराब के विरुद्ध राजस्व, पुलिस एवं आबकारी संयुक्त रूप से करें प्रभावी कार्रवाई : कलेक्टर डॉ. सोनवणे

■ आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्रतिदिन सुबह नाश्ता एवं थर्ड मील उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

बैतूल ,(निप्र)। घोड़ाडोंगरी विकासखंड की ग्राम पंचायत चोपना में आयोजित ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने चोपना सहित घोड़ाडोंगरी के विभिन्न ग्रामों के लिए नियुक्त जिला अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण की समीक्षा की। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सामने आई समस्याओं की जानकारी लेते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर डॉ सोनवणे ने नशे की समस्या पर अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर राजस्व, पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को प्रतिदिन निर्धारित समय पर सुबह का नाश्ता अनिवार्य रूप से मिले तथा थर्ड मील का वितरण भी नियमित रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों के पोषण से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि किसानों को ई-टोकन जनरेट कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए प्रत्येक गांव में 8 से 10 स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर इस कार्य से जोड़ा जाए, ताकि किसानों को स्थानीय स्तर पर ही सुविधा उपलब्ध हो सके। बैठक में ग्रामवार प्राप्त समस्याओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने ग्राम रामपुर में सोनभद्र नदी पर बैराज निर्माण, बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को पुनः चालू कराने, बीएसएनएल नेटवर्क की समस्या तथा जर्जर आंगनवाड़ी भवन की छत के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत गोलई बुजुर्ग में आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय निर्माण तथा ग्राम तेंदूमाल में सड़क पर जलभराव, नल-जल योजना एवं हैंडपंप के दूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए गांव को नल-जल योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत सातलदही के माध्यमिक विद्यालय में बिजली व्यवस्था बाधित पाए जाने पर कलेक्टर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं बंजारीढाल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा सातलदही से दुनावा तक पुलिया निर्माण संबंधी प्रकरणों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। ग्राम पंचायत आमडोह में राशन दुकानों द्वारा निर्धारित क्षेत्र से अधिक वितरण किए जाने के कारण उत्पन्न समस्याओं पर जिला आपूर्ति नियंत्रक को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नारायणपुर में ट्रांसफार्मर एवं पेयजल टैंकर की समस्या का शीघ्र समाधान करने को कहा। ग्राम नूतनडुंगा में प्रधानमंत्री आवास , सिंचाई, जर्जर आंगनवाड़ी एवं विद्यालय भवन से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। ग्राम चिकनपाटी में हैंडओवर हो चुके आयुष्मान आरोग्य मंदिर को आवश्यक संसाधनों के साथ शीघ्र प्रारंभ करने तथा सभी स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। ग्राम पंचायत झोली में नल-जल योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के गुणवत्ताहीन निर्माण तथा पुलिया निर्माण के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम सचिव की कार्यों के प्रति उदासीनता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि सात दिवस के भीतर लंबित कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में निलंबन की कार्रवाई की जाए। बैठक में ग्राम गोपीनाथपुर, खापा सहित अन्य ग्रामों से प्राप्त समस्याओं की भी समीक्षा कर संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

स्कूल के अतिरिक्त कक्ष निर्माण में देरी पर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक को नोटिस

बैतूल ,(निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने शुक्रवार को घोड़ाडोंगरी विकासखंड के ग्राम हीरापुर का भ्रमण कर विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान ग्रामीण सविता सोनी ने आवास एवं आजीविका से जुड़ी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। इस पर कलेक्टर ने ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता की जांच कर लाभ दिलाने तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम में संचालित किए जाने वाले रेशम केंद्र के संचालन के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम में नल-जल योजना बंद होने की शिकायत पर कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को तत्काल टीम भेजकर जल स्रोत एवं पाइपलाइन की जांच कर शीघ्र समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा रखी गई मार्ग निर्माण, मनरेगा मजदूरी भुगतान सहित अन्य समस्याओं पर भी संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पंचायत भवन के नियमित एवं व्यवस्थित संचालन के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। प्राथमिक शाला का निरीक्षण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण में देरी पर कार्रवाई कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने ग्राम हीरापुर की प्राथमिक शाला का निरीक्षण कर शैक्षणिक एवं आधारभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों से संवाद कर दर्ज छात्र संख्या की जानकारी ली तथा शिक्षकों को पर्याप्त रोशनी सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए शाला का सुव्यवस्थित संचालन करने और नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में निर्माणाधीन अतिरिक्त कक्ष का भी अवलोकन किया।

जल जमाव वाले स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था करें नगरीय निकाय

खाली प्लाटों पर जल जमाव न हो

हरदा ,(निप्र)। हंडिया नर्मदा घाट को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिये की जाए सतत निगरानीघंटा घर क्षेत्र होगा अतिक्रमण मुक्त, सुधरेगी यातायात व्यवस्थाजर्जर भवनों में स्कूल संचालित न होंरिंगरोड़ निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएसड़कों से पानी के की व्यवस्था करें पीडब्ल्यूडी - कलेक्टरहरदा 17 जुलाई 2026/ कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने बरसात के मौसम में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के दृष्टिगत खाली पड़े प्लाटों में जल जमाव न होने देने के निर्देश दिये हैं। उन्होने सभी नगरीय क्षेत्रों में जल जमाव वाले स्थानों पर जल निकासी की समूचित व्यवस्थाएं करने के लिये भी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है।

जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी ने बताया कि खाली पड़े जिन प्लाटों में जल भराव हो रहा है और मच्छर पनप रहे हैं, उन प्लाटों के मालिकों को नगर पालिका द्वारा नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पाबंद किया है कि जहां जल भराव हो रहा है, वहां मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिये फागिंग एवं अन्य आवश्यक उपाय किये जाएं। बैठक में उन्होने हंडिया नर्मदा घाट को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिये सतत निगरानी करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि जो दुकानदार प्लास्टिक फ्री व्यवस्था का उल्लंघन करते है, उन पर अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जाए। हरदा नगर के घण्टा घर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के भी बैठक में निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने कहा कि घण्टा घर क्षेत्र की व्यवस्था आमजन के लिये सुगम हो एवं यहां की यातायात व्यवस्था दुरूस्त रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि किसी भी सूरत में जर्जर भवनों में स्कूलों का संचालन न हो। कलेक्टर ने कहा कि हरदा नगर के बाहर से प्रस्तावित रिंग रोड़ निर्माण के कार्य में अवार्ड होने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसके निर्माण की कार्रवाई शीघ्र प्रारम्भ की जाए। उन्होने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को ताकीद किया कि सड़कों के निर्माण में पानी के निकास की व्यवस्था जरूर की जाए। कहीं भी सड़कों पर बरसाती पानी का भराव न हो, यह सुनिश्चित करें। बैठक में सड़कों पर विचरण करने वाले निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में शिफ्ट करने के भी निर्देश दिये गये। बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के समय सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश दिये गये। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली जोसेफ जोनाथन, अपर कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम कुमार, एसडीएम हरदा श्री अशोक डहेरिया, एसडीएम टिमरनी श्री शैलेन्द्र बड़ोनिया, एसडीएम खिरकिया सुश्री रजनी वर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बटकीडोह पंचायत में कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

■ पानी, सड़क, बिजली और नशे के मुद्दों पर दिए त्वरित कार्यवाही निर्देश

बैतूल ,(निप्र)। घोड़ाडोंगरी विकासखंड के भ्रमण के दौरान कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने ग्राम बटकीडोह के पंचायत भवन में आयोजित जनसंवाद में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने पेयजल, सड़क, बिजली, नशे की समस्या सहित अन्य स्थानीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं समय पर निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने ग्राम पंचायत को निर्देशित किया कि ग्रामीणों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्ययोजना का रिवाइज किया जाए, ताकि वास्तविक जरूरतों के अनुरूप विकास कार्य कराए जा सकें।

विद्यालय आने-जाने में विद्यार्थियों को हो रही कठिनाई का संज्ञान लेते हुए उन्होंने धरमपुर से बटकीडोह तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने पंचायत, विद्यालय, आंगनवाड़ी, मोक्षधाम सहित सभी सार्वजनिक परिसरों में व्यापक स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाने तथा लगाए गए पौधों का नियमित देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिले के सभी विद्यालयों में शौचालय एवं स्वच्छ पेयजल की बेहतर व्यवस्था हर हाल में उपलब्ध रहे। जनसंवाद के दौरान कलेक्टर डॉ सोनवणे ने ग्रामीणों से राशन वितरण, आंगनवाड़ी केंद्रों के नियमित संचालन तथा बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार की जानकारी भी ली और संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

ग्रामीणों द्वारा समग्र आईडी में पता संशोधन नहीं होने के कारण विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की समस्या बताने पर उन्होंने ग्राम पंचायत को निर्देश दिए कि ऐसे सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर दो दिनों के भीतर समग्र आईडी अपडेट कराना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम में युवाओं के नशे की लत की समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम भेजकर अवैध शराब के विरुद्ध सघन अभियान चलाने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों ने पंचायत में निर्मित टीन शेड की गुणवत्ताविहीन होने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित उपयंत्री (सब इंजीनियर) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

एसडीएम सुश्री रजनी वर्मा ने ली विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश

हरदा ,(निप्र)। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुश्री रजनी वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय खिरकिया में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न शासकीय विभागों के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। एसडीएम सुश्री रजनी वर्मा ने बैठक के दौरान सभी विभागों के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने और आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि और मंडी से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी तथा मंडी सचिव सहित विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

अमृत भारत स्टेशन योजना तहत पुनर्विकसित विदिशा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ

■ प्रधानमंत्री जी ने किया वर्चुअल उद्घाटनए यात्रियों को मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं

विदिशा ,(निप्र)। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के विदिशा रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिक स्वरूप में विकसित होकर यात्रियों की सेवा के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल आज रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। आधुनिक वास्तुशिल्प, अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं तथा दिव्यांगजन अनुकूल अधोसंरचना से सुसज्जित यह स्टेशन अब क्षेत्र के विकास, पर्यटन एवं आधुनिक भारतीय रेलवे की नई पहचान के रूप में स्थापित होगा।

विदिशा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से केंद्रीय किसान कल्याण तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जुड़े और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित कर रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है प्रधानमंत्री जी द्वारा विदिशा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के 75 रेलवे स्टेशनों में 13 रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के शामिल है, जिनका उद्घाटन किया गया है। विदिशा नगरी सांस्कृतिक आध्यात्मिकता का केंद्र है। आज अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करोड़ों देशवासियों का भविष्य बदल रहा है। इन सुंदर और भव्य स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ है। भारतीय रेल के बुनियादी ढांचे में तेज गति से क्रांतिकारी बदलाव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आया है।

विदिशा रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद श्री रजनीश अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य किये जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाना सहित वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। आधुनिक रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि भारत देश आधुनिक ट्रेन प्रारंभ करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केवल मध्य प्रदेश में 1 लाख करोड़ के कार्यालय रेलवे क्षेत्र में हुए हैंए आगे भी कार्य किए जाएंगे।

विकास कार्यों में कोई पूर्व कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कार्यक्रम को विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन ने भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि हमारे विदिशा का सौभाग्य है जो आज प्रधानमंत्री जी रेलवे स्टेशन की इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं जहां आधुनिक सुविधाएं मिलने जा रही हैं। उन्होंने विदेशी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में किए गए विभिन्न कार्यों को रेखांकित किया।

विदिशा रेलवे स्टेशन के लिए इतनी बड़ी सौगात के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी, मध्यप्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राम मोहन बघेल, श्री महाराज सिंह दांगी, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राकेश जादौन, विदिशा नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा के अलावा कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी, जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोडिया, समेत विभिन्न विभागो के अधिकारी, कर्मचारी, रेलवे एडीआरएम अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, विद्यार्थीगण, जनसमूह एवं रेलवे अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमो की प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव, मंत्रीगण सहित ई-बस से पहुंचे जगदीशपुर

ईंधन और शासकीय संसाधनों के मितव्ययी उपयोग का दिया संदेश, धरोहर प्रदर्शनी का किया शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्री परिषद की बैठक के लिए ई-बस से जगदीशपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में ईंधन, शासकीय संसाधनों के मितव्ययी उपयोग और सुशासन की भावना को साकार करते हुए मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ, सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री निवास से इलेक्ट्रिक बस से प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अनुकरणीय पहल के लिए अपने शासकीय वाहन और सुरक्षा काफिला सीएम हाउस में ही छोड़े। समस्त मंत्रीगण और उनका स्टाफ प्रातः 10 बजे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां से तीन इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से सामूहिक रूप से सभी बैठक स्थल के लिए रवाना हुए। इस दौरान मंत्रियों के व्यक्तिगत वाहन, पायलट और फॉलो वाहन जैसी सुविधाएं मुख्यमंत्री निवास में ही रोक दी गई।

वरिष्ठ अधिकारी अपने वाहनों के बजाय ई-बस से हुए रवाना

मंत्रिपरिषद बैठक में सम्मिलित होने वाले वरिष्ठ अधिकारीगण भी अपने वाहनों को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में छोड़कर प्रातः 10 बजे इलेक्ट्रिक बस से सामूहिक रूप से जगदीशपुर बैठक स्थल पहुंचें। यह पहल मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उस सोच को परिलक्षित करती है, जिसके अंतर्गत शासन के हर स्तर पर सादगी, मितव्ययिता और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।

जनजातीय नायकों और सुशासन पर केंद्रित रही प्रदर्शनी

मुख्यमंत्री निवास से चली ई-बसों के प्रति राजधानी वासी विशेष रूप से उत्सुक रहे, कई स्थानों पर ई-बसों पर पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मार्ग में पातरा पुल, लांबाखेड़ा और जगदीशपुर में प्रवेश पर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के जगदीशपुर पहुंचने पर विधायक श्री विष्णु खत्री ने अंग वस्त्रम से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का प्रवेश द्वार पर तिलक कर अभिवादन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर जगदीशपुर दुर्ग में लगाई गई धरोहर प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय कलाकारों से संवाद भी किया। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के जनजाति नायकों सहित सुशासन और शौर्य के पर्याय शासकों और राष्ट्रभक्तों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं।

प्रदेश में जोरदार तरीके से लौटा मानसून

24 घंटे में सागर-दमोह और रीवा में होगी झमाझम, 22 से इन इलाकों में मूसलाधार का खतरा

भोपाल (नप्र)। एमपी में मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। बंगाल की खाड़ी से आ रही प्रचुर नमी और मध्य भारत के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के चलते प्रदेश में बारिश का एक और नया दौर शुरू हो गया है। पूर्व मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार नायक के मुताबिक, आने वाले 7 से 10 दिनों तक पूरे प्रदेश में मानसून बेहद सक्रिय रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलेगी।

पूर्वी एमपी तरबतर, महाकोशल और बुंदेलखंड में भारी बारिश- पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी हिस्से में मानसून की सबसे ज्यादा सक्रियता देखी गई है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में सबसे ज्यादा 74.5 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बालाघाट के वारासिवनी में 69.3 मिमी, दमोह के पथरिया में 63 मिमी और सीधी-सिवनी में भी अच्छी बारिश दर्ज हुई है। पूर्वी हिस्से में हुई इस बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है।

पश्चिमी एमपी में बढ़ी उमस, रातें हुई गर्म

एक तरफ जहां पूर्वी मध्य प्रदेश बारिश से ठंडा हो गया है, वहीं पश्चिमी और उत्तरी जिलों (ग्वालियर-चंबल और मालवा) में अभी बारिश का इंतजार है। पिछले 24 घंटों में दतिया में पारा 38.6 डिग्री और ग्वालियर में 38 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज्यादा है। आसमान में बादलों के डेरे की वजह से रात्रिकालीन शीतलन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण श्योपुर, गुना और भोपाल में रातें काफी गर्म और उमस भरी दर्ज की जा रही हैं।

22 जुलाई से आ रहा है नया सिस्टम, इन संभागों में होगी भारी बारिश- मौसम मॉडल्स के संकेतों के मुताबिक, 20 से 23 जुलाई के बीच बारिश का यह दायरा धीरे-धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद 22 से 25 जुलाई के बीच उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दाब क्षेत्र बनने जा रहा है।

किसानों के लिए अमृत है यह बारिश, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में हो रही वर्षा खरीफ फसलों- विशेषकर सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द और मूंग के लिए अमृत के समान है। हालांकि, जिन इलाकों में भारी बारिश हो रही है, वहां किसानों को खेतों में जलभराव रोकने के लिए जल निकासी का इंतजाम करने की सलाह दी गई है।

17 दिन बाद केन-बेतवा के विरोध में चल रहे चिता आंदोलन खत्म

अमित भटनागर को भेजा गया अस्पताल

छतरपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन-बेतवा लिंक परियोजना से जुड़े विस्थापन और अन्य मांगों को लेकर पिछले 17 दिनों से चल रहा चिता आंदोलन शनिवार की सुबह जिला प्रशासन ने समाप्त करा दिया। सुबह करीब 6 बजे भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम धरना स्थल पहुंची। इसके बाद करीब एक घंटे तक आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। प्रशासनिक टीम में एडीएम विनय द्विवेदी, एएसपी आदित्य पाटले समेत छतरपुर और पन्ना जिले के एसडीएम स्तर के अधिकारी मौजूद थे।

नदी में उतर गए आंदोलनकारी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह 5 बजे से ही आंदोलनकारी बराना नदी में उतरकर प्रदर्शन करने लगे। कुछ लोग सांकेतिक रूप से बनाई गई चिताओं पर लेट गए, कुछ सूली और फांसी के फंदे का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने लगे। छतरपुर पुलिस और प्रशासन के पहुंचते ही कई प्रदर्शनकारी नदी के गहरे और तेज बहाव वाले हिस्से में चले गए।

एक घंटे की तनातनी के बाद आंदोलन समाप्त

करीब एक घंटे तक दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहा। इस दौरान प्रदर्शन कर रही महिलाओं को महिला पुलिसकर्मी धरना स्थल से हटाकर बाहर ले गईं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि इस दौरान कई महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की हुई, जिससे कुछ महिलाएं बेहोश हो गईं और कुछ को चोटें आईं।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर नदी में अपने साथियों के साथ डटे रहे। उन्हें बाहर लाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी नदी में उतरे, लेकिन तेज बहाव के कारण वापस लौटना पड़ा। बाद में काफी समझाइश के बाद अमित बाहर आए, जिसके बाद पुलिस उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले गई।

प्रशासन का पक्ष- एडीएम विनय द्विवेदी और एएसपी आदित्य पाटले ने बताया कि अमित भटनागर पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और इसके लिए उनकी सहमति भी ली गई। अमित भटनागर ने क्या कहा-अमित भटनागर ने आरोप लगाया कि प्रशासन इलाज के बहाने उन्हें धरना स्थल से हटाना चाहता था। उनके मुताबिक, यह प्रशासन के निरंकुश रवैये को दर्शाता है।

महिलाओं ने लगाए मारपीट के आरोप- धरने में शामिल महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और कई महिलाओं को घसीटकर हटाया गया, जिससे उन्हें चोटें आईं।

जमीन में दबा करोड़ों रुपए निकलेगा, नोटों की बारिश होगी

झांसे में आकर परिवार ने दिए लाखों, पोटली खोली तो निकले 20-20 के नोट

मंदसौर (नप्र)। नोटों की बारिश कराने और जमीन में गड़ा करोड़ों का खजाना निकालने का लालच देकर लाखों रुपए ऐंठने वाले एक फर्जी तांत्रिक गिरोह का मंदसौर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अफजलपुर थाना पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 51 हजार रुपए नकद, दो मोटरसाइकिल, तंत्र-मंत्र में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और एक मूर्ति बरामद की है। गिरोह के कुछ अन्य सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जगह-जगह दबिश दे रही है।

मंदसौर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इस ठगी का शिकार रतलाम जिले के चिकलाना गांव के रहने वाले गोपाल धाकड़ हुए हैं। आरोपियों ने खुद को बड़ा सिद्ध तांत्रिक बताकर गोपाल से संपर्क किया था। उन्होंने गोपाल को अपने झांसे में लिया और दावा किया कि वे अपनी तंत्र-मंत्र विद्या की मदद से नोटों की बारिश करा सकते हैं। साथ ही जमीन में बरसों से छिपा करोड़ों का खजाना भी बाहर निकाल सकते हैं।

सुनसान जंगल में रचा पूजा का नाटक- गोपाल को पूरी तरह अपने जाल में फंसाने के लिए आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। उन्होंने कुएं और जंगल जैसी सुनसान जगहों को

चुना और वहां तंत्र-मंत्र की पूजा का नाटक किया। पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने कुछ ड्रामे भी रचे। उन्होंने जंगल में जमीन के भीतर से अंबे माता की एक मूर्ति निकाली और गोपाल से कहा कि इस मूर्ति की 51 दिनों तक विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद यहां से भारी मात्रा में दबा हुआ धन निकलेगा। इसके बाद आरोपियों ने गोपाल को भूत-प्रेत का डर दिखाया और वहां से भेज दिया।

चमत्कार के झांसे में आकर पीड़ित गोपाल ने आरोपियों को लाखों रुपए दे दिए। रकम ऐंठने के बाद आरोपियों ने गोपाल को कपड़े में बंधी एक भारी पोटली सौंपी और हिदायत दी कि इसे सीधे अपने घर ले जाकर ही खोलना, तभी यह धन काम आएगा। गोपाल जब पोटली लेकर घर पहुंचे। उसे खोला तो उनके होश उड़ गए। पोटली में ऊपर और नीचे की तरफ तो कुछ असली नोट लगे थे, लेकिन बीच में सिर्फ 20-20 रुपए के नोटों की रद्दी गड्डियां भरी हुई थीं। धोखा होने का अहसास होते ही पीड़ित तुरंत पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।

उज्जैन डबल मर्डर केस में एक आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर

उज्जैन (नप्र)। नीलगंगा चौराहे पर शनिवार देर रात पुराने विवाद को लेकर गोरकर और पासी गुट आमने-सामने हो गए। पासी गुट के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने गोरकर परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। पथराव के बाद गोलियां की आवाज से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गोली लगने से गोरकर परिवार के दो युवक की मौत हो गई, जबकि उसी परिवार के दो लोग घायल हो गए।

एक आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर- वहीं, मामले में उज्जैन पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया है। पांच लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जिसमें एक महिला शामिल है। एक आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर भी किया गया है।

रात 12 बजे हुआ था विवाद- दरअसल, शनिवार देर रात करीब 12 बजे नीलगंगा चौराहे के समीप रहने वाले पहलवान नेता दिलीप राव गोरकर उर्फ दिल्लू पहलवान के परिवार के लोगों पर अचानक

पासी गुट के लोगों ने हमला कर दिया। देखते ही देखते ईंट और पत्थर चलने लगे। इसके बाद गोलियों की आवाज से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। गोली लगने से दिल्लू पहलवान के 32 वर्षीय भतीजे लोकेश पिता प्रदीप राव गोरकर और दूसरे भतीजे जितेश पिता प्रदीप राव गोरकर निवासी नीलगंगा की मौत हो गई। जबकि गोली और पत्थर लगने से दिल्लू पहलवान, उनके 32 वर्षीय पुत्र तपन गोरकर घायल हो गए।

लंबे समय से चल रहा था विवाद- नीलगंगा क्षेत्र में गोरकर और पासी गुट के लोगों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। बताया जाता है कि पूर्व में किसी विवाद में एक पक्ष के लोगों को सजा भी हो चुकी है। तब से ही दोनों गुटों के बीच रंजिश है। करीब दो महीने पहले भी दोनों गुटों के युवकों के बीच मारपीट हुई थी। यही पुराना विवाद शनिवार देर रात खूनी संघर्ष में बदल गया।

आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू- घटना के बाद तत्काल बाद एसपी प्रदीप शर्मा ने अलग-अलग पुलिस टीम बनाई और आरोपियों की धड़पकड़ शुरू कर दी। मामले में अब तक आठ लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी नरेश को जब पुलिस अन्य आरोपियों की निशानदेही के लिए ले जा रही थी, तब नरेश ने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनने का प्रयास किया। तभी बचाव कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और नरेश घायल हो गया है। नरेश के पैर में गोली लगी है जिसका उपचार चल रहा है।

तीन आरोपी हैं फरार

पुलिस ने जिन 8 लोगो के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है उनके नाम नरेश, राकेश, बंटी, लोकेश और मंजू है इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं, शेष 3 आरोपी रोशन, सन्नी और दुर्गेश फरार है।मामले में एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि रात्रि करीब 12 बजे दो पक्षों में विवाद हुआ था, गोरकर परिवार के दो लोगो की मौत हुई है और 2 लोग घायल है, हमला पासी परिवार के लोगों ने किया है। मामले में आठ लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर लिया है। पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। जिसमें एक महिला भी शामिल है। सबसे पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुरानी रंजिश का यह मामला है । दो माह पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। चार आरोपियों पर पूर्व के दो दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है।

कही-सुनी

360 के फेर में अटका मामला

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में भाजपा के 360 सदस्य करने की जुगत में लगे हैं। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व दो तिहाई स्पष्ट बहुमत का जुगाड़ कर लोकसभा की सीटों का परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास करवा लेना चाहती है। कुछ दल के सांसद बीजेपी से जुड़ भी गए हैं। कहते हैं 360 के चक्कर में न तो बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति हो पा रही है और न ही केंद्रीय मंत्रिमडल का विस्तार हो पा रहा है। केंद्र में फेरबदल न हो पाने के कारण राज्यों में भी बदलाव अटका है। छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन के बदलाव की हवा कई दिनों से चल रही है। राज्य के एक मंत्री और एक विधायक के केंद्रीय पदाधिकारी बनने की अटकलें चल रही है। दिल्ली में फेरबदल के बाद ही स्थिति साफ़ होगी। केंद्र में सहयोगी दलों को पुरस्कार मिलना तय माना जा रहा है। फार्मूला बनने और पिक्चर साफ़ होने के बाद छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भी सरकार में चेहरे बदल सकते हैं।

नकटी का खेल ही निराला

कहते हैं विधायकों को सस्ती दर पर जमीन देने के लिए नकटी गांव के लोगों को बेदखल करने का मामला सीधा और सरल नहीं है। मामला बड़ा पेचीदा है और इसमें कुछ राजनेताओं और बिल्डरों का स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है। नकटी गांव रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से काफी करीब है। बताते हैं नकटी गांव और उसके आसपास कुछ बिल्डरों की जमीन है। ये बिल्डर ऊँची पहुँच वाले हैं और राजनेताओं के करीब भी। सुनने में आ रहा है कि नकटी गांव और उसके आसपास एक बिल्डर की कई एकड़ जमीन है। बिल्डर बड़ा प्रोजेक्ट लाना चाहता है। विधायक कालोनी बन जाने से बिल्डर का प्रोजेक्ट सोना उगलने लगेगा। राज्य के एक मंत्री को इस बिल्डर का पार्टनर बताया जा रहा है। खबर है कि नकटी में एक अधिकारी की भी साढ़े 12 एकड़ जमीन है। प्रशासन ने अवैध कब्जा के आधार पर कुछ दिनों पहले नकटी गांव के लोगों की बसाहट को हटा दिया। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है। वह सदन के भीतर और सड़क पर इस मुद्दे पर ताकत दिखा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के आसपास एरोसिटी भी विकसित करना चाहती है। इस कारण भी बिल्डर नकटी और उसके आसपास के गांव को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मानकर चल रहे हैं।

सचिव और ओएसडी में तनातनी

कहते हैं एक सचिव और एक ओएसडी के बीच तनातनी चल रही है। सचिव और ओएसडी पहले भी साथ काम कर चुके हैं और दोनों के बीच ट्यूनिंग अच्छी मानी जाती थी। बताते हैं जब दोनों साथ काम करते थे, तब सचिव हाई लेवल पर नहीं थे और न ही नीति निर्धारक। अब सचिव महोदय काफी पावर में बताए जाते हैं। सुनने में आ रहा है कि दोनों के बीच एक निर्माण विभाग के कामकाज को लेकर तनातनी चल रही है। ओएसडी अपने मनमाफिक काम करवाना चाहते हैं। सचिव उसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं। ओएसडी को एक ठेकेदार ने पकड़ रखा है। ठेकेदार के कहे अनुसार ओएसडी साहब काम करवाना चाहते हैं। ये ठेकेदार बड़ा चर्चित है। यह ठेकेदार कुछ साल पहले एक निर्माण विभाग के मुखिया का चहेता था। मुखिया के नाम पर उस निर्माण विभाग में अपना सिक्का जमा रखा था। मुखिया रिटायर हो गए, तो अब ओएसडी साहब को पकड़ लिया है।

क्यों नहीं बदले बड़े जिले के एसपी ?

सरकार ने पिछले हफ्ते कुछ जिलों के एसपी बदले, पर दो-ढाई साल एक ही जिले में तैनात रहने वाले एसपी को इधर-उधर नहीं किया गया और न ही किसी को हटाया गया। कहते हैं सरकार बड़े जिलों के एसपी को इंटरचेंज करना चाहती थी, पर समीकरण फिट नहीं बैठ पाने के कारण मामला टल गया। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद पदस्थ कुछ एसपी अभी भी उसी जिले में तैनात हैं, तो कुछ डीआईजी बनने के बाद भी कप्तानी कर रहे हैं। चर्चा है कि सरकार अगले कुछ महीनों में बड़े जिलों के एसपी में हेरफेर की प्लानिंग कर रही है। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक पुलिस मुख्यालय स्तर पर बड़े आईपीएस अफसरों के प्रभार में भी बदलाव हो सकता है। गृह विभाग बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

सुर्खियों में भाजपा नेता

कहते हैं बीजेपी के नेता इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। कभी संगठन से जुड़े ये भाजपा नेता आजकल एक मंत्री के काफी करीबी बन गए हैं। मंत्री जी के पास कई विभाग हैं और सभी विभागों में भाजपा नेता की दखलंदाजी रहती है। चर्चा है कि मंत्री जी भाजपा नेता पर आँख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं और नेताजी चांदी काटने में लगे हैं। बाजार में हल्ला है कि नेताजी करोड़ों के आसामी बन गए हैं। भाजपा के भीतर ही खोजबीन चल रही है कि नेताजी मंत्री जी के इतने विश्वासपात्र कैसे बन गए और मंत्री जी उन पर इतना भरोसा कैसे करने लग गए हैं।

मानसून सत्र में अजय चंद्राकर की बैटिंग

छत्तीसगढ़ विधानसभा के 13 से 17 जुलाई तक चले मानसून सत्र में भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर ने अपना आक्रामक तेवर बरकरार रखा। लोगों को लग रहा था कि नई राजनीतिक परिस्थिति में अजय चंद्राकर थोड़ा धीरे चलेंगे। अजय चंद्राकर ने सवालों के माध्यम से कुछ मंत्रियों को घेरा तो टीका-टिप्पणी के जरिए विपक्ष कांग्रेस के सदस्यों को लपेटा। एक-दो मौकों पर तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तकरार हो गई और नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने अजय चंद्राकर पर सवाल दागे। मानसून सत्र में गर्माहट कम देखने को मिला। मंत्रियों का परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रहा। उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने भूपेश बघेल को पूर्व मुख्यमंत्री की जगह मुख्यमंत्री कह दिया, फिर भूल सुधार किया।

छवि बदलने की कोशिश में महंत

विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ ढ़ाई साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस ने आक्रामक होने के संकेत दिया, वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत भी नई भूमिका में आए। सहज,सरल और शांत स्वभाव के चरणदास महंत ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपनी नई छवि निखारने की कोशिश की। कांग्रेस ने साय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को घेरने की कोशिश तो की, पर कांग्रेस में एकजुटता की कमी दिखी। अविश्वास प्रस्ताव ढाई साल के सरकार के कामकाज के आसपास टिका रहा। कांग्रेस के सदस्यों से ज्यादा तेवर बीजेपी के सदस्यों ने दिखाया। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों को अपनी-अपनी बात कहने को मौका मिल गया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि ढाई साल बाद अविश्वास प्रस्ताव आया है तो 20-20 मैच की तरह होगा, पर चला टेस्ट मैच की तरह। कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों पक्ष की तरफ से 48 लोगों के बोलने की सूची बनी थी। पर लंबा खींचता देख कुछ कांट-छांट करने के बाद भी सदन सुबह तीन बजे तक चली।